04 - मोदी का दौराः आत्मनिर्भर भारत से वैश्विक शक्ति तक

05 - भोजशालाः इतिहास के आइने में सत्य की खोज

A Daily News Magazine

भोपाल

मंगलवार, 19 मई, 2026

06 - ओटीटी, रियलिटी शो : युवाओं की सफलता के बदलते मापदण्ड

07 - राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर कलेक्ट्रेट में दिलाई गई...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 256, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

वो आएगा नुमाइश ए सामान देखकर
क्यों कारोबार छोड़ दूं नुक़सान देखकर

नख़रे उठा रही हूं तुम्हारी तलाश के
रुकती नहीं हूं रास्ता वीरान देखकर

सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख़्स
मुंह फेर लेगा मुझको परेशान देखकर

वो तेरा लम्स वो तिरि बाहों की ख़ुशबुएं
लौटी हूं जैसे कोई गुलिस्तान देखकर

तू लाख बेवफ़ा है मगर सर उठा के चल
दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देखकर

ज़ाहिर न हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है
सबकी नज़र है तुझपे मेरी जान देखकर।

– हिमांशी बाबरा

प्रसंगवश

कमजोर मानसून व अल नीनो की दस्तक, भारत में बढ़ेंगी मुश्किलें

ललित मौर्य

सुबह खेत में खड़े किसान की नजर सबसे पहले आसमान पर जाती है, क्योंकि बादल सिर्फ पानी नहीं, उनके लिए सालभर की उम्मीद लेकर आते हैं। लेकिन इस बार वैज्ञानिक पहले ही चेता चुके हैं कि मानसून कम मेहरबान रह सकता है। ऊपर से प्रशांत महासागर के गर्भ में पनप रहा अल नीनो दुनिया के मौसम को बदलने की तैयारी में है, और इसका असर खेतों से लेकर रसोई तक महसूस हो सकता है।

अमेरिकी मौसम विज्ञान केंद्र की ताजा चेतावनी के मुताबिक, प्रशांत महासागर में 'अल नीनो' के पनपने की आहट तेज हो गई है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के मुताबिक मई से जुलाई 2026 के बीच इसकी शुरुआत की आशंका 82 फीसदी तक पहुंच चुकी है। इसके बाद सर्दियों तक जाते-जाते (दिसंबर 2026 से फरवरी 2027) तक इसके बने रहने की आशंका 96 प्रतिशत बताई गई है।

बता दें कि 12 मई 2026 को जापान के मौसम ब्यूरो ने इस बात की 90 फीसदी आशंका जताई है कि अल नीनों के गर्मियों तक उभरने का अंदेशा है।

पिछले कुछ महीनों से समुद्र की सतह का तापमान सामान्य के करीब बना हुआ था और स्थिति तटस्थ (ईएनएसओ-न्यूट्रल) थी। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने देखा है कि भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के भीतर सतह के नीचे लगातार गर्मी बढ़ रही है। यह संकेत है कि अल नीनो जल्द सक्रिय हो सकता है।

ताजा साप्ताहिक नीनो-3.4 इंडेक्स का मान +0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं, पश्चिमी हिस्से का नीनो-4 इंडेक्स +0.5 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी हिस्से का नीनो-1+2 इंडेक्स +1.0 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके साथ ही प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय हिस्से के नीचे का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। समुद्र के अंदर का तापमान पिछले छह महीनों से लगातार बढ़ रहा है।

इसका मतलब है कि भूमध्यरेखीय प्रशांत के बड़े हिस्से में समुद्र की गहराई में सामान्य से काफी अधिक गर्म पानी जमा हो रहा है। साथ ही, पश्चिमी भूमध्यरेखीय प्रशांत में निचले स्तर पर पश्चिमी हवाओं का दबाव देखा गया। ऊपरी वायुमंडल में यही स्थिति मध्य और पूर्व-मध्य प्रशांत तक फैली हुई है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो अल-नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्यीय क्षेत्र में घटने वाली उस मौसमी घटना का नाम है, जिसमें समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है और हवा पूर्व की ओर बहने लगती है। इसका प्रभाव न केवल समुद्र पर बल्कि वायुमंडल पर महसूस किया जाता है। यह मौसम का एक गर्म चरण है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहले से गर्म हो रही दुनिया को और ज्यादा गर्म कर सकता है।

जलवायु वैज्ञानिकों के मुताबिक इस घटना के चलते समुद्र का तापमान चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है।

सरल शब्दों में कहें तो जब मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से अधिक होने लगता है, तो उसे 'अल नीनो' कहा जाता है। यह बदलाव केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है। कई क्षेत्रों में सूखा बढ़ता है, कहीं बाढ़ आती है और खेती पर दबाव बढ़ जाता है। यह अपने साथ एक अनिश्चितता का संदेश लेकर आता है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अल नीनो बनने की संभावना अब पिछले महीने की तुलना में ज्यादा स्पष्ट है, लेकिन यह कितना शक्तिशाली होगा इसको लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। मौजूदा अनुमान के मुताबिक, किसी भी श्रेणी 'कमजोर, मध्यम या मजबूत' के अल नीनो के बनने की आशंका 37 फीसदी से अधिक नहीं है।

सबसे शक्तिशाली एल नीनो तब बनते हैं, जब गर्म समुद्र और वायुमंडल के बीच मजबूत तालमेल गर्मियों के दौरान लगातार बना रहे। 2026 में ऐसा होगा या नहीं, यह अभी तय नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका असर केवल बढ़ते तापमान तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी वजह से मानसून, खाद्य आपूर्ति और वैश्विक बाजारों पर भी असर पड़ेगा।

वैज्ञानिकों का कहना है कि शक्तिशाली अल नीनो का मतलब हमेशा बड़े असर नहीं होता। यह सिर्फ कुछ मौसमी बदलावों, जैसे सूखा या ज्यादा बारिश, की आशंका को बढ़ाता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी वजह से एशिया सहित दुनिया के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकता है।

मानसून के दौरान अल नीनो के उभरने का मतलब है कि एशिया के कई हिस्सों में बारिश कम हो सकती है, तापमान बढ़ सकता है और धान जैसी फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है। भारत में पहले ही मानसून के कमजोर रहने की आशंका जताई गई है।

जर्नल साइंस में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक अल नीनो के चलते भारत में मानसून का चरित्र बदल रहा है। भारत के सौ से अधिक वर्षों के बारिश से जुड़े आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि अल नीनो के दौरान सूखे क्षेत्रों में बारिश घट जाती है, जबकि नम क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होती है। इस अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि अल नीनो के दौरान नम इलाकों में भारी बारिश की आशंका 43 फीसदी तक बढ़ जाती है।

इससे पहले भी कई अल नीनो वर्षों के दौरान पूरे भारत में सूखा पड़ा था और मानसून के दौरान होने वाली बारिश में कमी आई थी। 2015 में भी 2023 की तरह ही अल नीनो की घटना घटी थी, जिसकी वजह से मॉनसूनी बारिश में 14.5 फीसदी की कमी आई थी। वहीं सिन्धु-गंगा के मैदानी क्षेत्र में होने वाली बारिश में 25.8 फीसदी की कमी दर्ज की गई थी। इसकी वजह से देश में सूखे की घटनाएं दर्ज की गई थी।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2026 की दूसरी छमाही में एशिया में ज्यादा गर्म और शुष्क मौसम देखने को मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा असर खेती पर पड़ेगा। धान जैसी फसलों की पैदावार घट सकती है। किसानों के सामने पहले से महंगे उर्वरक और ईंधन की समस्या है, ऐसे में मौसम की मार संकट को और गहरा कर सकती है।

भारत जैसे देशों के लिए यह चेतावनी अहम है क्योंकि भारतीय मानसून पर अल नीनो का सीधा असर पड़ता है। कमजोर मानसून से खेती, जल भंडार और खाद्य कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में यदि यह पूर्वानुमान सही साबित हुआ, तो 2026-27 केवल मौसम की कहानी नहीं होगा, बल्कि दुनिया की खाद्य सुरक्षा और महंगाई के लिए भी एक बड़ी परीक्षा बन सकता है।

(डाऊन टू अर्थ हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

नमाज नहीं रोकेंगे
...लेकिन सड़क पर भी नहीं होने देंगे

● *सीएम योगी का बड़ा ऐलान, बोले-जरूरी है तो शिफ्ट में पढ़िए*

कहा- प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी में बकरीद से एक हफ्ते पहले सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी ने चेतावनी दी है। लखनऊ में सोमवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा- सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। प्यार से मानेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। योगी ने कहा- नमाज पढ़नी है तो तय जगह पर पढ़िए। संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ लीजिए। हम नमाज नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। सड़कें नमाज पढ़ने या किसी तरह की भीड़ जुटाने के लिए नहीं हैं। उन्होंने कहा- लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यूपी में सड़कों पर नमाज होती है। मैं कहता हूं- कतई नहीं। सड़कें आम लोगों के चलने के लिए हैं। कोई भी आकर ट्रैफिक डिस्टर्ब करे, यह अधिकार किसी को नहीं है।

बरेली में लोगों ने हाथ आजमाया था, ताकत भी देख ली

सीएम योगी ने बरेली में हुए बवाल का भी जिक्र किया। कहा- बरेली में लोगों ने हाथ आजमाया था, ताकत भी देख ली। कानून सभी के लिए बराबर है। किसी को भी सड़क जाम करने या अव्यवस्था फैलाने की छूट नहीं दी जाएगी। दरअसल, यूपी में सितंबर 2025 में आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद हुआ था। बरेली में मुस्लिम नेता मौलाना तौकीर रजा ने नमाज के बाद धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया। पुलिस ने रोका तो पथराव हो गया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था।

पालघर में ट्रक-कंटेनर की टक्कर, 12 की मौत

● 25 घायल, ट्रक में 100 से ज्यादा लोग सवार थे सभी सगाई में जा रहे थे

पालघर (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर सोमवार को ट्रक और कंटेनर की टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक सवार 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक डहाणू तहसील के बापूगांव से 100 से ज्यादा लोग एक सगाई कार्यरक्रम में शामिल होने के लिए ट्रक में जा रहे थे। इसी दौरान पालघर जिले के धानीवरी गांव के पास सामने से आ रहे कंटेनर से ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई।

टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक और कंटेनर दोनों सड़क पर पलट गए। हादसे में ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद ट्रक में बैठे कई लोग उसके नीचे दब गए।

निगम, मंडलों के नवनियुक्त पदाधिकारियों के उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

आपके काम से ही बनेगी सरकार की पहचान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के निगम, मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण और आयोगों में नियुक्त अध्यक्ष-उपाध्यक्षों और सदस्यों भोपाल के अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया। अलग-अलग सत्रों में अधिकारियों ने प्रजेंटेशन दिए।

इसके बाद सीएम डॉ.मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ महेन्द्र सिंह, सुशासन संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राजीव दीक्षित ने संबोधित किया। इस प्रशिक्षण में कुल 63 नवनियुक्त नेताओं ने हिस्सा लिया।

हमारे द्वारा लिए गए निर्णय को तीसरी आंख भी देखती है: सीएम – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- कोई आपको उलझाएगा, उद्वेलित करेगा अलग-अलग प्रकार से प्रयास करेगा तो इन सबसे बचना आपको ही है। इसमें कोई दूसरा कोई आपका मददगार नहीं होगा। आप ही जवाबदार हैं। सोशल मीडिया बहुत बारीकी से देखता है। हमारे द्वारा लिए गए निर्णय को तीसरी आंख भी देखती है।

पहले एक-दो महीने काम समझिए और सीखिए। काम में डूबेंगे तो रास्ता भी मिलेगा। नियम कानून के दायरे में रहकर काम करें। अपने निकाय को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। अहंकार को लाएंगे तो कष्ट होगा। छोटा-बड़ा कोई नहीं है। काम करते-करते आपको किसी को रोक भी सकते हैं कि आप यह काम कर रहे हैं अब आपको ये नहीं करना है। आप कहेंगे सरकार में लगाना है तो सरकार में लगा लेंगे, आप कहेंगे वापस दे दो तो वापस दे देंगे।प्रशिक्षण सत्र के उद्घाटन सत्र में सीएम डॉ. मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह, सुशासन संस्थान के उपाध्यक्ष प्रो राजीव दीक्षित प्रशिक्षण के दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का ग्रुप फोटो भी हुआ।

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बोले- दुखी मन से छोटी-मोटी कार्रवाई करनी पड़ती है

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा- विगत दिनों कुछ घटनाएं हुईं इसलिए बड़े दुखी मन से कोई छोटी-मोटी कार्रवाई करनी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उनकी अपेक्षा है कि हम ताकतवर हों लेकिन ताकत का उपयोग आम जनता और कार्यकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए करें।

खंडेलवाल बोले- मेरिट पर आपका चयन हुआ- बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा- आज किसी विशिष्ट जिम्मेदारी के कारण आप सब यहां मौजूद हैं। आप सब का चयन विभिन्न विभागों के निगम, बोर्ड आयोग प्राधिकरण में चयन हुआ। और कहीं न कहीं आप उस पद के योग्य थे पार्टी ने भी आपको इस योग्य समझा। यह बड़ी बात है कि सभी लोगों का मेरिट पर चुनाव हुआ।

खंडेलवाल ने कहा- यदि संगठन आपसे कोई अपेक्षा करता है तो उसे जरूर पूरा करें। क्योंकि हजारों कार्यकर्ताओं में आपका चयन हुआ है। जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी के साथ-साथ यदि संगठन आपसे कोई अपेक्षा करता है, कोई क्षेत्र दे या कोई आदेश दे तो उसपर अमल करें। कहीं ऐसा न हो कि वो ताकत सिर्फ हमारी अपनी बन जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनहित सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिक मास चल रहा है।

प्रदेश प्रभारी बोले : नेतृत्व अपील करे तो आदेश का इंतजार न करें, अमल में लाएं

बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा- आप सबको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब आप छतरी के नीचे आ गए हैं। अब मुख्यमंत्री जी को आपकी रोज रिपोर्ट मिलेगी। आप क्या कर रहे हैं? आपका आचरण व्यवहार क्या है? आपके परिवार का इन्वॉलवमेंट कितना है? आपसे बोर्ड निगम को फायदा हो रहा या नुकसान हो रहा है? आपकी परफॉर्मेंस का आंकलन सरकार भी करेगी और संगठन भी करेगा।आप अकेले इसी भूमिका में नहीं रहेंगे। आपको बहुत बड़ा काम मिलने वाला है। अपना फेसबुक, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक्टिव रखिए। राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्देश दे, उसका तुरंत पालन करें। आदेश की प्रतीक्षा न करें। अनुशासन जीवन का आभूषण है। पुरुषोत्तम मास में आपका प्रशिक्षण हो रहा है, उस पुरुषोत्तम की छाया अपने ऊपर पड़नी चाहिए। सादगी से रहना चाहिए। एक साथ इतनी नियुक्तियां भारत के किसी राज्य में आज तक नहीं हुईं।

अब नॉर्वे ने दिया पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान

● विश्व भर में पीएम का ये 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान ● मोदी बोले- यूरोप भारत में 100 अरब निवेश करेगा

ओस्लो (एजेंसी)। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। यह नॉर्वे के सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। इसे मिलाकर अब तक पीएम मोदी को 32 अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले कल स्वीडन ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था।

पीएम मोदी ने आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नॉर्वे के पीएम योनास स्टोरे के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ था।

पीएम मोदी के मुताबिक, यह समझौता भारत और नॉर्वे के बीच साझा विकास और समृद्धि का मजबूत आधार बनेगा। इस समझौते के तहत अगले 15 साल में भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियां पैदा करने का टारगेट रखा गया है।

नॉर्वे बोला-

भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ साझेदारी जरूरी- नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओस्लो दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता, तनाव और संघर्ष के दौर में उन देशों के साथ रिश्ते मजबूत करना जरूरी है, जिनके साथ समान मूल्यों और हितों को साझा किया जाता है। स्टोरे ने कहा कि दुनिया में इस समय काफी तनाव और अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे समय में उन देशों के साथ रिश्ते मजबूत करना जरूरी है जिनकी सोच और मूल्य एक जैसे हों।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 19 मई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

चिकित्सा व्यवसाय नहीं, मानव सेवा का है माध्यम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

स्वास्थ्य विभाग एवं सेवांकुर भारत प्रकल्प के बीच हुआ एम.ओ.यू.

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मरीज की चिकित्सा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, यह मानव सेवा का एक माध्यम है। हमें ऐसे चिकित्सक तैयार करने है, जो मानव सेवा और मरीज की सेवा के लिये तत्पर हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में आयोजित एक समझौता ज्ञापन बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल की उपस्थिति में राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग तथा सेवांकुर भारत, डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान, छत्रपति संभाजी नगर (महाराष्ट्र) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर आदान-प्रदान किया गया। एमओयू की अवधि 5 वर्ष की है। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश को सेवा-प्रधान स्वास्थ्य नेतृत्व का मॉडल राज्य बनाना है। एमओयू का मुख्य लक्ष्य सेवा-प्रधान डॉक्टरों की ऐसी पीढ़ी तैयार करना है, जो व्यवसायिक ही नहीं, समाज में परिवर्तन के वाहक भी बनें। यह एमओयू अनुभव-आधारित शिक्षण व मूल्य-आधारित नेतृत्व विकास अर्थात् सेवा के जरिये सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें एक सप्ताह देश के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, जिसमें लगभग 300 प्रतिभागियों को छत्रपति संभाजीनगर में गहन प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस कार्यक्रम के बाद निरंतर सहभागिता के लिए अनुभव साझा सत्र एवं व्यक्तित्व विकास शिविर भी आयोजित किये जायें। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल सहित सेवांकुर भारत प्रकल्प के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान की स्थापना वर्ष 1989 में समाज के प्रति समर्पित चिकित्सकों द्वारा की गई थी। विगत तीन दशकों में संस्था ने 70 लाख से अधिक वंचित एवं जरूरतमंद रोगियों को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं करुणामय चिकित्सा सेवा प्रदान की है। संस्था का केंद्र बिंदु डॉ. हेडगेवार रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) है, जो सेवाभाव, सादगी एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता के साथ आम जन तक उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिये प्रतिबद्ध है। वर्तमान में प्रतिष्ठान देशभर में 46 एकीकृत परियोजनाओं का संचालन कर रहा है, जिनमें संभाजीनगर, नासिक एवं शिवसागर (असम) के बहु-विशेषज्ञता अस्पताल, चिकित्सा, नर्सिंग एवं फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, एशिया का अग्रणी अत्याधुनिक रक्तपेढी; तथा झुग्गी बस्ती एवं ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजनाएँ सम्मिलित हैं। हृदय शल्य चिकित्सा, आईवीएफ, नवजात शिशु देखभाल, एमआरआई एवं कैथ लैब जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ-साथ संस्था महिला एवं बाल विकास, टीकाकरण अभियान और जन स्वास्थ्य जागरूकता जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में सोमवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और महाराष्ट्र के सेवाकुंर भारत, डॉ.. बाबा साहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान, छत्रपति संभाजी नगर के मधुआ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर आदान-प्रदान हुआ।

संक्षिप्त समाचार

बाइक सवार ग्रुप ने संघ मुख्यालय के पास की फायरिंग

- सीसीटीवी में कैद हुई घटना, खुलासे के बाद मचा हड़कंप

नागपुर (एजेंसी)। महाराष्ट्र के नागपुर से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। बाइक सवार युवकों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्यालय की तरफ को खुलेआम फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। कुछ दिन पहले नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के संवेदनशील जोन में विस्फोटक की बरामगी हुई थी। अब इस घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ कर दिए हैं। सीसीटीवी के कैद हुई फुटेज में छह

बाइक सवार फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है तो वहीं नागपुर के महल में कोठी रोड इलाके में फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में दहशत और डर का माहौल बन गया। यह क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हेडक्वार्टर के काफी नजदीक है। संघ का मुख्यालय रेशीम बाग में स्थित है।

दो राउंड फायरिंग का खुलासा

नागपुर के महल क्षेत्र के कोठी रोड इलाके में दो राउंड फायरिंग की गई। पुलिस ने आगे कहा कि रवि मोहतो, गंगा काकड़े और दूसरे आरोपियों का ड्रग ट्रैफिकिंग और गैर-कानूनी सामान रखने के मामलों में पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड को देखते हुए जांच जारी है।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना रविवार यानी 17 मई को रात करीब 11.30 बजे हुई।

थलापति विजय ने भी निकाल लिया बुलडोजर

पेरम्बूर में 30 फुट चौड़ी सड़क बनाकर 30 साल पुरानी मांग कर दी खत्म

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सीएम जोसेफ विजय का पहला बुलडोजर ऐक्शन सामने आया है। अपने पहले एक हफ्ते में एक के बाद एक कई फैसले लेने के बाद अब थलापति विजय का बुलडोजर ऐक्शन सुर्खियों में आया है। मुख्यमंत्री विजय ने अपने चुनाव क्षेत्र पेरम्बूर में 30 साल पुरानी मांग को सीएम की कुर्सी संभालने के बाद पहले हफ्ते में ही पूरा कर दिया है। थलापति विजय के निर्देश पर पेरम्बूर में छात्रों के लिए 30 फुट चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते के बनने के बाद अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी।

पेरम्बूर में सामने आया 'बुलडोजर ऐक्शन'

सिनेमा की दुनिया से निकल सियासत में चमके विजय विधानसभा चुनावों में दो सीटों से चुनाव लड़े थे। वह पेरम्बूर और त्रिची से जीते थे। विजय ने पेरम्बूर सीट अपने पास रखी है। यह सीट तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का ही हिस्सा है। यह उत्तरी भाग में स्थित है। यह चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से सात किलोमीटर की दमरी पर स्थित है। पेरम्बूर कोच फैक्ट्री से चर्चा में है।

टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, तीन की मौत

ड्राइवर को झपकी आई और बाइक पर चढ़ गया टैंकर, मासूमों ने मौके पर दम तोड़ा

इंदौर (नप्र)। इंदौर के धार रोड स्थित हाईलिंक कॉलोनी के सामने सोमवार सुबह हुए सड़क हादसे में एक मां और उसके दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। परिवार के छह लोग (तीन वयस्क-तीन बच्चे) एक ही बाइक पर सवार होकर पगड़ी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मां ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही चंदन नगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। दोनों

बच्चों के शव जिला अस्पताल भेजे गए, जबकि महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया।

बेसन कांटा फोड़ जा रहे थे- मृतकों के परिजन लखन देवड़ा ने बताया कि उनका बड़ा बेटा अशोक देवड़ा (30), बहू अनिता देवड़ा (28), उनके बच्चे वैष्णवी उर्फ वेशू (4), रोहन (2), संतोषी (1) और भांजा राजेश बाइक पर सवार होकर औरंगपुरी से देवास जिले के बबलू ग्राम बेसन कांटा फोड़ जा रहे थे। परिवार मूल रूप से देवास जिले के उदयनगर का रहने वाला है। अनिता के भाई के निधन के बाद आयोजित पगड़ी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी निकले थे। अशोक देवड़ा ए-1 प्लस डोर प्लाई डोर कंपनी मुरादपुर औरंगपुरी में काम करता है और परिवार के साथ वहीं रहता है।

भाई की पगड़ी के कार्यक्रम में जा रहे थे

लखन देवड़ा ने बताया कि बहू के भाई की पगड़ी के कार्यक्रम में जाने के लिए निकले थे। मगर कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। घटना के बाद परिवार में गम का माहौल है। चर्चा करते हुए लखन देवड़ा भी भावुक हो गए। दोनों मासूम बच्चों को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा, जबकि मां का शव पीएम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया। जहां उनका पीएम किया जा रहा है।

बंगाल सरकार ने महिलाओं के लिए खोला खजाना

- हर महीने 3000 रुपए, बस में यात्रा भी होगी फ्री

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में सीएम सुवेंदु ने कैबिनेट की दूसरी बैठक में महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना और फ्री बस सेवा को मंजूरी दे दी। इस योजना के लागू होते ही बंगाल की महिलाओं को एक जून से हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही एक जून से सभी महिलाएं सरकारी बसों में

मुफ्त में सफर कर सकेंगी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग का भी राज्य सरकार ने गठन किया है। हालांकि, दूसरी कैबिनेट बैठक में बकाया डीए पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इसके अलावा मंत्री अग्निमित्रा पाल ने बताया कि जिन महिलाओं का नाम लक्ष्मी भंडार में है उन्हें नए तरीके से अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं, मदरसा को मिलने वाले तमाम सरकारी सहायता को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसमें इमाम और मोअज्जिम को मिलने वाला मासिक भत्ता भी शामिल है। इसके अलावा 2011 से राज्य में ओबीसी आरक्षण सूची का दोबारा जांच कराने की भी बात कही गई है। अब हर 15 दिन में एक बार बैठक होगी।

कार में दम घुटने से 4 वर्षीय बच्ची की मौत

इंदौर में दादा-दादी के साथ गई थी वर्कशॉप लौटते वक्त गाड़ी में ही सो गई मासूम

इंदौर (नप्र)। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र की नंदनवन कॉलोनी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां चार साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। वह अपने दादा-दादी और अन्य बच्चों के साथ कार से वर्कशॉप गई थी। वहां से लौटते समय वह कार में ही सो गई थी। घर पहुंचने पर सभी लोग कार से उतर गए, लेकिन बच्ची कार में ही सोती रह गई। काफी देर तक नजर नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। बाद में वह कार में बेसुध हालत में मिली। परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम

कर सोमवार को बच्ची का पोस्टमॉर्टम कराया। प्रारंभिक तौर पर दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने मंत्रालय में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यों की समीक्षा की।

वीडी सतीशन बने केरलम के नए सीएम, ली शपथ

- पूरी कैबिनेट के साथ ली शपथ राहुल-प्रियंका रहे मौजूद

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के 13वें मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उनके अलावा पूरी कैबिनेट (20 मंत्रियों) को शपथ दिलाई। ऐसा 64 साल के बाद हुआ। इससे पहले राज्य के तीसरे कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे आर शंकर ने 1962 में पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी, लेकिन 1964 में अविश्वास प्रस्ताव के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। कार्यक्रम में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन, बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी कार्यक्रम में शामिल हुए। केरलम की कैबिनेट में 14 विधायकों ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली।

'सुप्रीम' उवाच, जमानत अधिकार है, जेल अपवाद

एससी ने कहा- उमर खालिद को मिल सकती थी जमानत

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले अपने पिछले फैसले पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने सोमवार को यह बयान सैयद इफ्तिखार अंद्राबी से जुड़े नार्को-टेररिज्म मामले पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने माना कि किसी आरोपी को बेल

देना एक नियम है, उसे जेल भेजना अपवाद होना चाहिए। जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने केए नजीब मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में माना था कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अदालतें यूएपीए मामलों में जमानत दे सकती हैं।

- **कोर्ट बोला- छोटी बेंच को बड़ी बेंच के फैसले मानने पड़ेंगे-** सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब कोई बड़ी बेंच फैसला सुना देती है तो छोटी बेंच को उसे मानना ही पड़ेगा। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि छोटी बेंच सीधे-सीधे मना तो नहीं करतीं, लेकिन घुमा-फिराकर बड़े फैसले के असर को कमजोर कर देती हैं। इस साल 4 जनवरी को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने फैसले को रीव्यू करने से भी मना कर दिया था।

यूपी में टीचर-इंजीनियर समेत 10 लोगों की मौत

- ट्रक ने मैजिक को टक्कर मारी, कई लोग सीट के बीच में ही फंस गए

लखीमपुर-खीरी (एजेंसी)। लखीमपुर खीरी में सोमवार सुबह 7.30 बजे मैजिक वाहन और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई। ये सभी मैजिक वाहन में सवार थे। 9 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों में सरकारी टीचर और इंजीनियर भी शामिल हैं। हादसा जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर पीलीभीत-बस्ती हाईवे पर अदलीसपुर गांव के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मैजिक वाहन लखीमपुर से सिसैया की तरफ से जा रहा था। इसे बहराइच से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मारी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मैजिक में बैठे लोगों के सिर फट गए। लोग सीट के बीच में ही फंस गए। दो लोग उछलकर बाहर रोड पर गिरे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है।

नीट पेपर लीक मामला

अब अभिभावकों पर भी शिकंजा कस रही सीबीआई

नई दिल्ली (एजेंसी)। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले का दायरा अब बढ़ते-बढ़ते छात्रों के घर तक पहुंच गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम ने हाल के दिनों में जांच के दौरान कई ऐसे माता-पिता से भी पूछताछ की, जिन पर कथित तौर पर लीक हुए प्रश्न पत्र खरीदने का आरोप है। जानकारी के अनुसार, सीबीआई की आठ अधिकारियों वाली एक टीम ने शनिवार और रविवार को तीन से चार अलग-अलग जगहों पर तलाशी ली। इनमें नांदेड़ के विद्युत नगर इलाके में स्थित एक घर और लातूर की कुछ जगहें शामिल हैं। यह तलाशी तब ली गई, जब एजेंसी को यह जानकारी मिली कि इन परिवारों ने कथित तौर पर अपनी बेटियों के लिए नीट के लीक हुए पेपर हासिल किए थे।

नांदेड़ से लातूर तक मची खलबली, हर ओर हड़कंप

पेपर के लिए बिचौलियों को दिए 5 से 10 लाख रुपए- अधिकारियों को शक है कि परीक्षा से पहले लीक हुए पेपर पाने के लिए उन्होंने बिचौलियों को 5 से 10 लाख रुपये के बीच की रकम दी थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह रैकेट पेपर बनाने वालों और बिचौलियों के मुख्य नेटवर्क से भी आगे तक फैला हुआ था। इसमें आर्थिक रूप से संपन्न ऐसे माता-पिता भी शामिल थे, जिन्होंने कथित तौर पर अपने बच्चों का मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पक्का करवाने के लिए बड़ी रकम चुकाई थी। अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई की टीम शुक्रवार को नांदेड़ पहुंची और उसने तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने उस छात्रा के माता-पिता से पूछताछ की, जिसने 3 मई को नीट यूजी की परीक्षा दी थी। अधिकारियों ने बताया कि माता-पिता से आठ घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की गई।

कई निजी कोचिंग संस्थान के नाम भी आए सामने- एक निजी कोचिंग संस्थान ने नांदेड़ में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों की तस्वीरों वाले फ्लेक्स बैनर लगाए थे। उसका नाम भी आया है।

खंगाले जा रहे फोन कॉल और मैसेज का ब्योरा

सीबीआई अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, दस्तावेजों और संचार से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की। इनमें परिवार के सदस्यों के बीच हुई फोन कॉल और मैसेज का ब्योरा भी शामिल था। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि नांदेड़ वाले मामले में, छात्रा के पिता (जो एक व्यवसायी हैं) ने लीक हुए पेपर हासिल करने के लिए लगभग 10 लाख रुपये चुकाए थे। इसमें से 5 लाख रुपये एक बिचौलिए को और 5 लाख रुपये किसी दूसरे व्यक्ति को दिए गए थे। जांच टीम छात्रा के पुणे स्थित एक कोचिंग संस्थान से संबंधों की भी जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि वह लगभग 15 दिनों तक संस्थान में रुकी थी।

जूनियर और युवक रेडक्रॉस शाखा की समीक्षा बैठक में हुए शामिल

विद्यार्थियों को रेडक्रॉस के सिद्धांतों से करें संस्कारित : राज्यपाल पटेल

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि रेडक्रॉस के सिद्धांत बच्चों में सेवा, सद्भाव, करूणा और संवेदनशीलता विकसित करते हैं। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। उनका सर्वांगीण विकास कर, उन्हें आदर्श नागरिक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए सक्षम पीढ़ी के निर्माण के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों में रेडक्रॉस की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सभी शिक्षण संस्थानों को हर विद्यार्थी को रेडक्रॉस से जोड़ने की ज़िम्मेदारी उठाना चाहिए।

राज्यपाल श्री पटेल सोमवार को रेडक्रॉस की मध्यप्रदेश राज्य शाखा इकाई द्वारा आयोजित जूनियर रेडक्रॉस एवं युवक रेडक्रॉस शाखा की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक का आयोजन होटल पलाश रेसीडेंसी में किया गया। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल श्री पटेल ने ईंधन बचत के दृष्टिगत अपने कारकेड के वाहनों की संख्या को आधा कर दिया है।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान, बच्चों में ज्ञान और संस्कार को प्रदान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। संस्थानों को विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। उन्हें समसामयिक चुनौतियों और जीवन की प्रतिस्पर्धाओं के लिए जुझारू बनाएं। सफलताओं के दबाव और तनाव प्रबंधन से निपटने का हुनर सिखाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में बच्चों और युवाओं का विशेष योगदान रहेगा। ऐसे में विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोड़ना होगा। कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। आदर्श नागरिक बनाकर मानवता के ध्वजवाहक के रूप में तैयार करना होगा।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान, प्रदेश और जिला रेडक्रास इकाईयों के साथ सक्रिय समन्वय करें। रेडक्रॉस की वार्षिक गतिविधियों का कैलेंडर अनुसार नियमित आयोजन करें। उन्होंने देश के अन्य राज्यों में रेडक्रॉस के नवाचारों का अध्ययन कर प्रदेश की परिस्थिति के अनुरूप समावेश करने की बात कही। राज्यपाल श्री पटेल ने जूनियर और युवक रेडक्रॉस के लिए गठित समिति को शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। प्रदेश के सभी जिलों में रेडक्रॉस की गतिविधियों को सक्रियता के साथ संचालित करने के लिए कहा है।

बैठक में जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह ने रेडक्रॉस के माध्यम से ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सेनेटरी नैपकिन को कम दाम पर उपलब्ध कराने के संबंध में विचार के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और निचले स्तर पर कम से कम दामों में सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने से कमजोर वर्ग की महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा। आर्थिक बचत के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य का स्तर भी बेहतर होगा। उच्च शिक्षा मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में जूनियर और युवक रेडक्रॉस की गतिविधियों के सतत आयोजन की बात कहीं। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों में भी रेडक्रॉस, एन.सी.सी. और एन.एस.एस. के माध्यम से मिलने वाले प्रोत्साहनों के संबंध में चर्चा की। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने स्कूल स्तर पर जूनियर और युवक रेडक्रॉस के पंजीयन, सदस्यता आदि प्रक्रियाओं के लिए सक्रिय समन्वय की आवश्यकता बताई।

राज्यपाल 4 कारकेड वाहनों के साथ पहुँचे

राज्यपाल श्री पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर अपने कारकेड के वाहनों की संख्या आधी कर दी है। राज्यपाल श्री पटेल सोमवार को जूनियर और युवक रेडक्रॉस की बैठक में शामिल होने के लिए केवल 4 वाहनों के साथ कार्यक्रम स्थल पहुँचे। विदित हो कि राज्यपाल के कारकेड में पूर्व में 8 वाहन शामिल रहते थे। राज्यपाल श्री पटेल का बैठक के प्रारंभ में रेडक्रॉस की मध्यप्रदेश राज्य शाखा के चेयरमैन डॉ. श्याम सिंह कुमरे ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। जनरल सेक्रेटरी श्री रामेंद्र सिंह ने जूनियर और युवक रेडक्रॉस के पंजीकरण, शुल्क निर्धारण, वार्षिक ऑडिट, निर्धारित गतिविधियों के आयोजन आदि प्रस्तावों की जानकारी दी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, श्री अनुपम राजन और राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, उच्च और स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा शासकीय विश्वविद्यालय के कुलगुरु उपस्थित थे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की।

जनजातीय अंचल में 3-डी उन्मूलन के लिये बड़वानी पुलिस की पहल

दारू, दहेज और डीजे मुक्त विवाह के लिये चलेगा अभियान

भोपाल (नप्र)। जनजाति अंचल में पनप रही कुरीतियों के खिलाफ एक अनोखी पहल देखने को मिली, जब बड़वानी में पुलिस अधीक्षक स्वयं विवाह समारोह में पहुँचे। इस अवसर पर उन्होंने '3डी' अर्थात दारू, दहेज और डीजे जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन का संकल्प दिलाया। यह विवाह केवल दो परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की मिसाल बन गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी ने लोगों को यह संदेश दिया कि समाज सुधार केवल कानून से नहीं, बल्कि जनभागीदारी और जागरूकता से संभव है। समारोह में उपस्थित लोगों ने भी 3डी मुक्त विवाह का समर्थन करते हुए सादगी और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया।

पुलिस अधीक्षक बडवानी श्री पद्म विलोचन शुक्ल के नेतृत्व में विगत माह से जिला पुलिस बडवानी द्वारा जिले में विवाह समारोह में दहेज, डीजे एवं दारू का उपयोग नही करने हेतु 3डी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस

विभाग की अभिनव पहल से प्रेरित होकर गत 4 मई को ग्राम धवली में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित जनसंवाद में ग्राम जुनापानी के श्री रामा नरगावे द्वारा अपने तीनों बच्चो के विवाह समारोह में दहेज, डीजे एवं दारू का उपयोग नही करने का संकल्प लिया था। श्री रामा नरगावे द्वारा 17 मई को अपने पुत्र कृष्णा नरगावे, पुत्री रंजिता नरगावे एवं दिना नरगावे का विवाह समारोह बिना दहेज, डीजे एवं दारू के संपन्न किया गया। श्री रामा नरगावे व्दारा पुलिस अधीक्षक बडवानी श्री पद्म विलोचन शुक्ल को अपने बच्चों के विवाह समारोह में आमंत्रित करने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम जुनापानी विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। उन्होंने दुल्हा-दुल्हनों को शुभकामना संदेश एवं उपहार देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। श्री शुक्ल ने नरगावे दंपति को शॉल-श्रीफल देकर उनकी साहसिक पहल के लिये सम्मानित किया। विवाह समारोह में सम्मिलित जनजातीय समाज के लोगों ने भी सालों से चली आ रही सभी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लिया। भविष्य में बिना दहेज, डीजे एवं दारू के विवाह समारोह सम्पन्न कराने तथा दहेज नही लेने व देने की कुरीति को पूर्ण रूप से बंद करने का संकल्प दिलाया गया। विवाह समारोह में थाना वरला का पुलिस स्टाफ तथा वन मंडल अधिकारी सेंधवा श्री इंदुसिंह गडरिया एवं गायत्री परिवार के सदस्य श्री खुमसिंह तथा ग्राम सरपंच पटेल भी शामिल हुए।

पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या पार्टी करने गए थे, देर रात कनपटी में बंदूक रखकर दोस्त ने किया हमला

रीवा (नप्र)। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक सनसनी मामला सामने आया है। यहां एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके गांव में तनाव का माहौल है। मामला जिले के सामान थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़ारिया मोहल्ले का है। रविवार देर रात यहां एक पुलिसकर्मी की उसके ही दोस्त ने गोली मारकर हत्या कर दी।

देर रात 1 बजे गोली मारकर हत्या– इसी दौरान रात करीब 1 दोस्त ने कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने की क्या वजह थी अभी अब अज्ञात है। घायल पुलिस कर्मी को संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा में अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी ने अस्पताल में चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। मृतक पुलिसकर्मी एक बेटी और बेटा है।

मौके पर पहुंचे अधिकारी– घटना की सूचना मिलती ही सामान थाना पुलिस एवं विभाग की आलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। आरोपियों की तलाश कर हत्या की मुख्य वजह पता करने में जुटे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

करीबी दोस्त ने की हत्या

पुलिसकर्मी राकेश कुमार पटेल रविवार रात घर से दोस्त के यहां पार्टी करने के निकले थे। हत्या का आरोप पुलिसकर्मी के एक करीबी दोस्त पर लगा है। घटना के बाद से दोस्त फरार है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मैहर जिले के रामनगर थाना में पदस्थ पुलिसकर्मी राकेश कुमार पटेल अपने गांव गए थे।

पुलिस ने मामला दर्ज किया

पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हत्या के कारण का अभी खुलासा नहीं हुआ है। आरोपी की तलाश की जा रही है। उसके बाद कारण सामने आएगा। शव को पोस्टमार्ट्म के लिए भेज दिया गया है।

शेयर बाजार में बूम आने वाला है, दोगुना होगा मुनाफा !

लालच देकर 50 लाख की साइबर ठगी

गुना (नप्र)। शेयर मॉर्केट और क्रिप्टो करंसी में निवेश और दिन दूना रात चौगुना के लालच में एक व्यापारी के बेटे ने 5 दिन में 50 लाख रुपए गंवा दिए। मामला गुना के एक व्यापारी से जुड़ा है। जानकारी अनुसार उसके बेटे को बहुत ही सस्ते रेट पर शेयर खरीदने का लालच दिया गया था।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार मटकरी कॉलोनी में रहने वाले एक प्रतिष्ठित व्यापारी के बेटे के साथ ऑनलाइन साइबर ठगों द्वारा करीब 50 लाख रुपए की बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शातिर ठगों ने युवक को एक फर्जी क्रिप्टो करंसी कंपनी के जरिए बेहद सस्ते दामों पर शेयर खरीदने और भारी मुनाफे का प्रलोभन दिया था। पीड़ित परिवार की शिकायत पर गुना कोतवाली पुलिस ने अज्ञात जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है।

क्रिप्टो करंसी 4 के नाम पर ऐसे बिछाया जाल

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मटकरी कॉलोनी निवासी 53 वर्षीय श्याम अग्रवाल पिता चोखरमल अग्रवाल ने कोतवाली थाने में इस पूरे फर्जीवाड़े की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक, यह पूरा खेल पिछले साल 26 जून को शुरू हुआ था। उनके बेटे आयुष अग्रवाल के मोबाइल पर एक तथाकथित क्रिप्टो करंसी कंपनी की तरफ से सस्ते दाम पर शेयर खरीदने का झांसा देने वाला मैसेज आया था। अधिक मुनाफे के लालच में आकर आयुष कंपनी के बिछाए जाल में फंस गया।

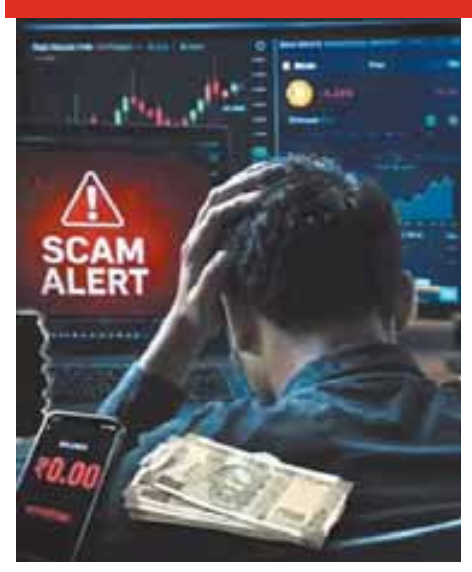

5 दिन में ट्रांसफर कराए 49.47 लाख रुपए

ऑनलाइन ठगों की प्लानिंग इतनी सटीक थी कि उन्होंने आयुष को संभलने का मौका ही नहीं दिया। 26 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच, महज 5 से 6 दिनों के भीतर शातिर ठगों ने आयुष से एचडीएफसी,एक्सिस, एसबीआई और आईसीआईसीआई, बैंक के दर्जनों अलग-अलग खाता नंबरों में कुल 49 लाख 47 हजार 264 रुपये डलवा लिए। ठग इतने शातिर थे कि वे हर बार नया खाता नंबर देकर कभी 50 हजार, कभी 3 लाख तो कभी 12 लाख रुपये जैसी बड़ी रकमें ट्रांसफर करवाते रहे।

पैसे विड्रॉ न होने पर चल 'फर्जीवाड़े' का पता

इस बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ तब हुआ, जब 1 जुलाई को लगातार मोटी रकम निवेश करने के बाद आयुष अग्रवाल को कंपनी की कार्यप्रणाली पर गहरा शक हुआ। जब आयुष ने निवेश की गई अपनी पूरी रकम वापस निकालनी चाही, तो कंपनी के पोर्टल से पैसे 'विड्रॉ' नहीं हुए।

50 हजार रुपए और जमा करने का मैसेज आया

इसके विपरीत, कंपनी की तरफ से आयुष के मोबाइल पर 50 हजार रुपए और जमा करने का एक नया मैसेज भेज दिया गया। जब आयुष ने और पैसे डालने से साफ मना कर दिया और अपनी पुरानी रकम वापस मांगी, तो ठगों ने उससे संपर्क पूरी तरह काट दिया। खुद को ठगा महसूस होने पर पीड़ित ने पूरी बात अपने पिता को बताई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने की शरण ली।

रिटायर्ड जज सास ने आवेदन में लिखा-ड्रग एडिक्ट थी ट्विशा

गिरीबाला सिंह का आरोप– बहू लापता भी रही, हर महीने देते थे पैसे

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित बागमुगालिया एक्सटेंशन में रिटायर्ड महिला जज की बहू ट्विशा शर्मा की आत्महत्या का मामला उलझता जा रहा है। घटना के छह दिन बाद भी मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है।

परिवार आरोपी सास गिरीबाला सिंह को मिली जमानत से नाराज है और न्याय की मांग पर अड़ा हुआ है। इसी बीच मामले में नया मोड़ तब आया, जब आरोपी सास गिरीबाला सिंह की ओर से जिला कोर्ट में दाखिल जमानत आवेदन के कुछ हिस्से सामने आए।

आवेदन में गिरीबाला सिंह ने बहू ट्विशा शर्मा को ड्रग एडिक्ट बताया है। उन्होंने कोर्ट में दावा किया कि ट्विशा को नशे की लत थी। जब उसे नशा नहीं मिलता था तो उसके हाथ कांपने लगते थे। वह चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगती थी। गिरीबाला सिंह ने इन तथ्यों का जिक्र अपनी जमानत याचिका में किया है।वहीं, समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

12 घंटे लापता रही थी ट्विशा– गिरीबाला सिंह के जमानत आवेदन में लिखा गया है कि बहू ट्विशा 17 अप्रैल 2026 की सुबह बाय फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हुई। 18 अप्रैल 2026 को मायके पहुंची। करीब 12 घंटे लापता रही। पूछने पर ट्विशा ने नहीं बताया कि वह कहां रही। ट्विशा चार तेलुगु फिल्मों में एक्ट्रेस

के तौर पर काम कर चुकी थीं। इसी के साथ वह एड फिल्मों में काम करने के साथ ही मॉडलिंग भी कर चुकी थीं।

ब्यूटी पार्लर से लौटते ही मां का कॉल आया

11 मई की शाम ट्विशा ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर घर लौटी थी। टीवी देखने के दौरान ही मां का कॉल आ गया। बात करते हुए वह छत पर पहुंची थी। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। रात करीब साढ़े दस बजे ट्विशा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

प्रेग्नेंट होते ही बदल गया व्यवहार

गिरीबाला सिंह के वकील ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान तर्क दिए कि ट्विशा गर्भवती थी। प्रेग्नेंट होते ही ससुराल पक्ष के लिए उसका रवैया बदल गया था। वकील ने यह भी तर्क दिया कि ससुराल पक्ष अपनी प्रेग्नेंट बहू का इलाज करा रहे थे।

महँगाई के खिलाफ भाकपा का विरोध प्रदर्शन 25 मई को

भोपाल। पेट्रोल, डीजल और सांची दूध की मूल्य वृद्धि के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आगामी 25 मई को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन कर स्थानीय जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्य मंत्री के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। भाकपा ने पेट्रोल , डीजल और सांची दूध की कीमतों में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग की है।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने बताया कि पार्टी की भोपाल में आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक में तत्संबंधी निर्णय लिया गया। भारत में गरीबी, बेरोजगारी,महंगाई से त्रस्त जनता पर पेट्रोल, डीजल और सांची दूध की कीमतों की वृद्धि का भार डालना अनुचित है। पेट्रोल, डीजल की कीमत में भारी वृद्धि के लिए केन्द्र और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य 25 मई को विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में पेट्रोलियम पदार्थों पर मध्य प्रदेश सरकार का टैक्स कम करने की मांग की जाएगी ताकि जनता को आंशिक राहत मिल सके ।

एमपी में ओटीएफ के लिए युवा कांग्रेस करेगी आंदोलन

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए वन टाइम फीस (ओटीएफ) लागू करने की मांग तेज हो गई है। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं से ओटीएफ लागू करने का वादा किया गया था।

लेकिन सरकार बनने के बाद इसे लागू नहीं किया गया। इसी मांग को लेकर 17 जून से ग्वालियर से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने कहा कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो, एक बार फीस ली जाए, छात्र बार-बार फीस नहीं देंगे। राजस्थान का मॉडल एमपी में भी लागू किया जाए। मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने कहा कि 17 जून को ग्वालियर से 'रन फॉर ओटीएफ' अभियान की शुरुआत होगी। इसके बाद मध्यप्रदेश के सभी जिलों में पदयात्रा, मशाल जुलूस और जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों पर भर्ती परीक्षाओं की फीस का बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। एक छात्र सालभर में अलग-अलग परीक्षाओं के आवेदन पर करीब 10 हजार से 15 हजार तक खर्च कर देता है।

17 जून को ग्वालियर से शुरू होगा, सरकार को याद दिलाएगी चुनावी वादे

सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान युवाओं से ओटीएफ लागू करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। संगठन ने कहा कि जब तक छात्रों और युवाओं को राहत नहीं मिलती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

छात्रों पर आर्थिक बोझ का दावा

युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने कहा कि प्रदेश में एक परीक्षा के लिए औसतन 400 से 500 तक आवेदन शुल्क लिया जाता है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर, ग्रामीण और वंचित वर्ग के छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

संपादकीय

ट्रंप की निष्फल चीन यात्रा!

मनमौजी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच कर 9 साल बाद चीन की यात्रा पर गए थे और इससे उन्हें क्या हासिल हुआ, सिवाय चीन की हां में हां मिलाने के, इस पर दुनिया भर के कूटनीतिक विशेषज्ञ मंथन कर रहे हैं। ट्रंप अपने साथ 17 उद्योगपतियों का बड़ा दल भी साथ लेकर गए थे। दोनों देशों के बीच और खुद ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिन पिंग के बीच सीधी बातचीत हुई, लेकिन ठोस नतीजा कुछ भी नहीं निकला। दरअसल इस दौरे की शुरूआत ही परस्पर अविश्वास से हुई थी और अंत भी उसी तर्ज पर हुआ। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी लोग अपने मोबाइल लैपटॉप आदि घर पर छोड़कर गए थे, क्योंकि उन्हें शंका थी कि चीन उनमे कुछ जासूसी डिवाइस फिट कर सकता है। अविश्वास की इंतिहा ये थी कि बेनतीजा दौर से लौटते समय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने चीन द्वारा दिए सारे गिफ्ट और उपहार भी एयरपोर्ट पर छोड़ दिए। इसके पीछे भी डर वही था। हालांकि ऐसा करना किसी भी मेजबान देश का अपमान करना भी है। बताया जाता है कि ट्रंप-चिनफिंग समिट में ईरान युद्ध, ताइवान, ट्रेड, टैरिफ, रेयर अर्थ मिनरल्स, एआई और चिप जैसे संवेदनशील मुद्दे छाए रहे। चीन ने तो इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि लेकिन ट्रंप ने दावा किया चर्चा में दोनों देशों ने कई समस्याएं सुलझाई हैं और रिश्ते पहले से मजबूत हुए हैं। लेकिन कौन से रिश्ते मजबूत हुए हैं, इसका कोई ठोस विवरण उन्होंने नहीं दिया। ट्रंप के मुताबिक चीन 200 बोइंग जेट खरीदने और अमेरिका में सैकड़ों अरब डॉलर के निवेश करने पर राजी हुआ है। वहीं, ईरान युद्ध पर उनकी और चिनफिंग की सोच में समानता है। ट्रंप के अनुसार दोनों नेता चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, हॉर्मुज रास्ता खुला रहे और ईरान परमाणु हथियार विकसित न कर पाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि चिनफिंग ने ईरान युद्ध सुलझाने में मदद की इच्छा जताई है और ईरान को हथियार न देने का भरोसा भी दिया। हालांकि, इन दावों की चीन ने कोई पुष्टि नहीं की है। चीन ने बयान में व्यापक सहयोग, स्थिरता व शांति की बात दोहराई। ट्रंप की नाकामी यह है कि इतने हाई प्रोफाइल दौरे के बाद भी वो कठोर सौदेबाज चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग से कुछ भी नहीं हासिल नहीं कर सके। ट्रंप की कोशिश थी कि चीन होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए ईरान पर दबाव डाले। लेकिन शी ने ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया। दूसरे, ट्रंप चाहते थे कि चीन के साथ कोई बड़ा व्यापारिक समझौता हो। वह भी नहीं हुआ। केवल वर्तमान व्यापार सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों देशों की एक परिषद बनाने पर सहमति बनी। चीन ने अमेरिका को खास रियायतें देने में भी रूचि नहीं दिखाई। उल्टे ताइवान पर कब्जाने की अपनी मंशा साफतौर पर जता दी। इसको लेकर ट्रंप इतने दबाव में दिखे कि उन्होंने कह दिया कि ताइवान पर चीनी हमला हुआ तो वह उस ताइवान की कतई मदद नहीं करेगा, जिसकी सुरक्षा की गारंटी उसने पिछ्ले 80 सालों से दी हुई है और जिसे लोकतंत्र के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाता रहा है। उधर चीनी राष्ट्रपति ने तो अमेरिका को 'पतनशील देश' तक कह दिया, जिसका ट्रंप विरोध तक नहीं कर सके। उल्टे अपनी खीज छिपाने के लिए उन्होंने इस कथन को मोड़ने की कोशिश की कि शी ने यह कमेंट पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर किया था।

नजरिया

अंशुमान

लेखक संसद टीवी से सम्बद्ध पत्रकार हैं।

मोदी का दौरा: आत्मनिर्भर भारत से वैश्विक शक्ति तक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 से 20 मई 2026 तक होने वाली यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा केवल एक सामान्य विदेशी दौरा नहीं है, बल्कि यह बदलती दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत, आत्मविश्वास और वैश्विक भूमिका का बड़ा संकेत है। आज जब पूरी दुनिया कई बड़े बदलावों से गुजर रही है। कहीं युद्ध और तनाव बढ़ रहे हैं, कहीं ऊर्जा संकट गहरा रहा है, तो कहीं व्यापार और तकनीक को लेकर देशों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। ऐसे समय में भारत खुद को केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद, स्थिर और उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है।

पिछ्ले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर एक संदेश एकदम साफ गया है कि भारत ने अपनी विदेश नीति को पूरी तरह नए अंदाज में आगे बढ़ाया है। अब भारत केवल औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह ऐसे संबंध बनाना चाहता है जिनसे देश को सीधे आर्थिक, तकनीकी, सामरिक और रणनीतिक लाभ मिले। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा उसी सोच का हिस्सा है। यह दौरा दिखाता है कि भारत अब दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर अपने राष्ट्रीय हितों को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है।

भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। दुनिया की बड़ी कंपनियां अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं और उन्हें एक ऐसे देश की जरूरत है जहां बड़ा बाजार, मजबूत लोकतंत्र, स्थिर सरकार और विशाल युवा आबादी मौजूद हो। भारत इन सभी क्षेत्रों में मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। यही वजह है कि यूरोप और खाड़ी देशों की दिलचस्पी भारत में लगातार बढ़ रही है।

भारत मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के जरिए खुद को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब बनाने की कोशिश कर रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल समझौते करना नहीं है, बल्कि दुनिया को यह संदेश देना भी है कि भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का एक अहम केंद्र बनने जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। दुनिया के कई विकसित देशों में कामकाजी उम्र की आबादी घट रही है, जबकि भारत के पास करोड़ों युवा हैं जो तकनीक, उद्योग, रिसर्च और सेवा क्षेत्रों में दुनिया की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसी कारण विदेशी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाने को लेकर उत्साहित हैं।

ना सिर्फ रणनीतिक बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो भारत अब केवल आयात करने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि वह निर्यात बढ़ाकर दुनिया की सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहता है। कोरोना महामारी और खास तौर रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया ने यह समझा कि किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में भारत खुद को एक भरोसेमंद और स्थिर विकल्प के रूप में पेश कर रहा है।

यूरोप और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर यह समझौता सफल होता है तो भारतीय उद्योगों को यूरोप के बड़े बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी। इससे भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटोमोबाइल, आईटी और कृषि क्षेत्रों को बड़ा फायदा हो सकता है। साथ ही यूरोपीय निवेश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर को नई गति दे सकता है।

इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में भी यह यात्रा भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वैसे-वैसे ऊर्जा की जरूरत भी बढ़ रही है। लंबे समय तक भारत तेल और गैस के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहा, लेकिन अब भारत ऊर्जा के नए और सुरक्षित विकल्प तैयार करना चाहता है। भारत ने पिछ्ले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल के जरिए भारत दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में नेतृत्व देने की कोशिश कर रहा है। यूएई, नॉर्वे और यूरोपीय देशों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और क्लीन टेक्नोलॉजी में सहयोग भारत को भविष्य की ऊर्जा ताकत बनाने में मदद कर सकता है।

यूएई की यात्रा इस पूरे दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान के बीच मजबूत व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंधों ने दोनों देशों की साझेदारी को नई ऊंचाई दी है। पहले भारत और यूएई का रिश्ता मुख्य रूप से तेल और वहां रहने वाले भारतीयों तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब यह रिश्ता रणनीतिक साझेदारी में बदल चुका है। आज यूएई भारत का बड़ा निवेशक बन रहा है। बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, फूड कॉरिडोर, डिजिटल पेमेंट, फिनटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई में रहने वाले लाखों भारतीय दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। भारत के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे, क्योंकि वहां किसी भी तनाव का असर सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

भारत अब केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि वह पश्चिम एशिया में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार बनना चाहता है। यही कारण है कि भारत खाड़ी देशों के साथ रक्षा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में भी संबंध मजबूत कर रहा है। नीदरलैंड के साथ भारत का सहयोग तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर आज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक बन चुका है। मोबाइल, कंप्यूटर, एआई और रक्षा उपकरणों तक हर क्षेत्र में चिप्स की जरूरत है। भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है और नीदरलैंड की तकनीकी विशेषज्ञता इसमें मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा जल प्रबंधन में भी नीदरलैंड दुनिया के सबसे अनुभवी देशों में गिना जाता है। भारत के कई राज्यों में बाढ़ और जल संकट जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में दोनों देशों का सहयोग भारत के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है।

स्वीडन भारत के लिए एक आधुनिक और इनोवेशन आधारित साझेदार के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री उल्फ हजलमार क्रिस्टर्सन का भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर जोर यह दिखाता है कि यूरोप भारत को भविष्य की वैश्विक शक्ति के रूप में देख रहा है। स्वीडन और भारत रक्षा निर्माण, एआई, 5जी, हरित तकनीक और स्टार्टअप सेक्टर में मिलकर काम करना चाहते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। भारतीय युवाओं ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। यही कारण है कि यूरोपीय कंपनियां भारत के साथ मिलकर भविष्य की तकनीकों में निवेश करना चाहती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से भी इस दौरे की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक मानी जा रही है। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप अपनी आर्थिक और रणनीतिक नीतियों में बड़े बदलाव कर रहा है। पिछ्ले कुछ वर्षों में यूरोप ने महसूस किया है कि किसी एक देश, खासकर चीन, पर जरूरत से ज्यादा आर्थिक निर्भरता भविष्य में जोखिम पैदा कर सकती है। इसी कारण अब यूरोपीय देश ऐसे भरोसेमंद और स्थिर साझेदारों की तलाश कर रहे हैं जिनके साथ लंबे समय तक मजबूत आर्थिक और तकनीकी सहयोग किया जा सके। नॉर्वे की यात्रा इस पूरे दौरे के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक मानी जा रही है। चार दशक से भी ज्यादा समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नॉर्वे जाना केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि भारत अब नॉर्डिक देशों के साथ अपने रिश्तों को नई मजबूती देना चाहता है। पिछ्ले कुछ वर्षों में भारत ने यह समझा है कि भविष्य की वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में केवल बड़ी सैन्य शक्तियां ही नहीं, बल्कि तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में आगे रहने वाले देशों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। नॉर्वे ऐसे ही देशों में शामिल है।

नॉर्वे दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जो स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में काफी आगे हैं। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उसे आने वाले वर्षों में बड़ी मात्रा में ऊर्जा, नई तकनीक और हरित विकास मॉडल की जरूरत होगी। ऐसे में नॉर्वे भारत के लिए एक उपयोगी और भरोसेमंद साझेदार बन सकता है। दोनों देश ग्रीन हाइड्रोजन, पवन ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था और क्लीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

इस दौरे में इटली की यात्रा भी एक बेहद रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से होने वाली है। पिछ्ले कुछ वर्षों में भारत और इटली के रिश्तों में नई गर्मजोशी और मजबूती देखने को मिली है। दोनों देशों ने यह समझा है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करना दोनों के हित में है। इटली यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, रक्षा और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उसकी मजबूत पहचान है। भारत चाहता है कि इटली की कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाएं और मेक इन इंडिया अभियान का हिस्सा बनें। इससे भारत को नई तकनीक, आधुनिक उत्पादन प्रणाली और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।

दूरगामी और आत्मनिर्भरता की नीति पर अग्रसरित भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पूरी तरह विदेशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। पिछ्ले कुछ वर्षों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से काम किया है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के तहत सरकार देश में ही रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा दे रही है। स्वच्छ ऊर्जा और विज्ञान के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा और विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत और इटली के बीच सहयोग बढ़ सकता है। आज पूरी दुनिया प्रदूषण कम करने और ग्रीन एनर्जी अपनाने पर जोर दे रही है। भारत भी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और दूसरी स्वच्छ तकनीकों को तेजी से बढ़ावा दे रहा है। इटली को हरित तकनीक और नए औद्योगिक प्रयोगों का अच्छा अनुभव है, जिससे भारत को काफी फायदा मिल सकता है।

भारत आज ऐसी विदेश नीति अपना रहा है जिसमें वह अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों, रूस और एशिया के अन्य देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत किसी एक गुट का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के जरिए हर देश के साथ अपने हितों के अनुसार संबंध मजबूत करना चाहता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया अब भारत को केवल एक विकासशील देश के रूप में नहीं देख रही, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में देख रही है जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और तकनीक में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की यह पांच देशों की यात्रा इसी बदलते भारत और उसकी बढ़ती वैश्विक पहचान का मजबूत संदेश देती है।

व्यवस्था और संवेदनाओं को राख करती आग

जलती यात्री बसें

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।

रात का दूसरा पहर था। प्रदेश के दो बड़े नगरों के बीच चलने वाली बस राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज़ी से दौड़ी चली जा रही थी। खिड़कियों के बाहर अंधेरे खेत पीछे छूट रहे थे और भीतर पीली रोशनी में यात्रियों की अपनी-अपनी छोटी दुनियाएँ बसी थीं। कोई मोबाइल पर धीमे स्वर में बात कर रहा था, कोई ऊँघ रहा था, तो कोई सीट से सिर टिकाकर आने वाले कल के सपने देख रहा था।

बस की पिछली सीट पर चार वर्षीय नन्हा बालक अपनी माँ की गोद में सोया हुआ था। उसकी छोटी उंगलियाँ अब भी खिलौना कार को कसकर पकड़े थीं। माँ कभी उसके माथे को चूमती, कभी खिड़की से बाहर झाँकती। पिता सामने वाली सीट पर बैठे मुस्कुरा रहे थे– 'ग्वालियर पहुँचकर इसे किला दिखाऊँगा,' उन्होंने धीरे से कहा था।

अचानक बस के अगले हिस्से से चिंगारियों की तेज़ आवाज़ आई– 'छटाक... छटाक... !' कुछ ही सेकंड में धुएँ की कड़वी गंध फैलने लगी। तभी इंजन के पास से लपटें उठीं और देखते-ही-देखते आग ने प्लास्टिक के सामान को पकड़ लिया। एक भयावह चीख बस में गूँज उठी– आग... आग लग गई! नींद में डूबे लोग घबराकर उठे। धक्का-मुक्की शुरू हो गई। कोई खिड़की तोड़ने लगा, कोई बच्चों को उठाकर दरवाज़े की ओर भागा। जलते प्लास्टिक से उठता काला धुआँ साँसों को जला रहा था। बस के भीतर अफरा-तफरी का ऐसा दृश्य था मानो हर व्यक्ति मौत से आगे निकल जाना चाहता हो। बच्चे की माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया। पिता पीछे की ओर भागे, लेकिन तभी किसी ने चीखकर कहा– पीछे से रास्ता बंद है! बस में आपातकालीन गेट था ही नहीं।

आग अब विकराल हो चुकी थी। प्लास्टिक के पैकेट पिघल-पिघलकर जलते तेल की तरह फर्श पर बह रहे थे। धुआँ इतना घना हो गया कि चेहरों की पहचान मिटने लगी।

किसी तरह पिता ने पत्नी को दरवाज़े तक पहुँचा दिया। बाहर खड़े लोग हाथ बढ़ाकर यात्रियों को खींच रहे थे। तभी माँ की गोद अचानक हल्की हो गई। बालक... अंदर रह गया था। 'मेरा बच्चा... ! मेरा बच्चा अंदर है... !' उसकी चीख रात के सन्नाटे को चीरती चली गई। उसकी आँखों के सामने बस धधक रही थी और भीतर उसका मासूम बेटा–जो कुछ देर पहले खिलौना कार पकड़े मुस्कुरा रहा था। कुछ मिनटों बाद सब शांत हो गया। बस अब सिर्फ जलता हुआ ढाँचा थी। सड़क पर धुआँ तैर रहा था। यात्रियों की सिसकियाँ हवा में घुली थीं। दूर कहीं उस बालक की छोटी खिलौना कार सड़क किनारे पड़ी थी–आधी जली हुई, आधी बची हुई। उस रात केवल एक बच्चा नहीं मरा था। मर गई थी व्यवस्था की लापरवाही। मर गई थी यात्रियों की सुरक्षा के प्रति संवेदनहीनता। और जल गई थी वह उम्मीद कि हर सफर सुरक्षित होकर घर तक पहुँचता है। सुबह अखबारों में खबर छपी– शार्ट सर्किट से बस में आग, एक मासूम की मौत। लेकिन उन चार-पाँच शब्दों के पीछे एक माँ की टूटी हुई दुनिया थी, एक पिता की असहाय आँखें थीं, और एक नन्हा सपना था... जो ग्वालियर का किला देखने से पहले ही राख बन गया।

आप इसे एक मार्मिक कहानी कह लें लेकिन यात्री बसों में लगने वाली आग के बाद लगभग ऐसा ही कुछ घटित होता है। फिर वही होता है जो हमेशा से होता रहा है। सरकारें मुआवजा देनें की घोषणाएं करती हैं। नियम कानूनों की उपेक्षा की जांच और दोषियों को सजा देने का वायदा किया जाता है। थोड़े दिनों बाद किसी और घटना का समाचार पढ़ने को मिल जाता है। यात्री वाहनों और बसों में आग लगने की बढ़ती घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। हाल के महीनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसी ही कई डरा देने वाली खबरें सामने आई हैं। सफर को सुरक्षित बनाने के लिए इन हादसों के मूल कारणों को समझना, प्रशासनिक कमियों को पहचानना और कड़े कदम उठाना बेहद जरूरी है।

हाल ही (मई 2026) में इंदौर से ग्वालियर जा रही एक इंटरसिटी बस में शार्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। अधिकांश यात्री तो समय रहते बाहर निकल आए, लेकिन आपातकालीन गेट न होने और बस में प्लास्टिक का व्यावसायिक सामान लोड होने के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि एक 4 वर्षीय मासूम बच्चा अंदर ही फंस गया और उसकी जान चली गई। इसी प्रकार (मई 2026) में हैदराबाद से तिरुपति जा रही एक निजी ट्रैवल्स की बस का पिछला टायर जाम होने के कारण घर्षण (Friction) पैदा हुआ और टायर ब्लास्ट के साथ आग लग गई। गनीमत रही कि ड्राइवर की सूझबूझ से सभी 36 यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया, लेकिन बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। मार्च में इसी राज्य के मार्कापुरम में एक बस और ट्रक की टक्कर के बाद लगी आग में 14 लोगों की मौत हो गई थी। अप्रैल 2026 में इंदौर से सागर जा रही एक स्लीपर कोच बस के स्टेयरिंग के पास शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसमें 50 यात्री बाल-बाल बचे। वहीं मैनपुरी में भी एक चलती रोडवेज बस में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी थी।

दरअसल, वाहनों में आग लगने के कई कारण सामने आते रहे हैं, जैसे आधुनिक बसों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, एसी (AC), हैवी लाइट्स और म्यूजिक सिस्टम के लिए अतिरिक्त वायरिंग की जाती है। यह काम अक्सर अप्रशिक्षित मैकेनिकों से और घटिया क्वालिटी के तारों से करवा लिया जाता जाता है। अत्यधिक गर्मी में लोड बढ़ने पर तार आपस में चिपक जाते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कई बार गर्मियों में सड़क का तापमान बहुत ज्यादा होता है। यदि टायर पुराने हों, उनमें हवा का दबाव सही न हो, या ब्रेक शू (Break Shoe) जाम होने के कारण पहिया रगड़ खा रहा हो, तो भयंकर घर्षण से टायर आग पकड़ लेते हैं। इंजन का रखरखाव ठीक नहीं होने से भी दुर्घटना का खतरा बन जाता है, इंजन में ऑयल या फ्यूल लीक होना, कूलेंट का कम होना और समय पर सर्विसिंग न होने से इंजन ओवरहीट हो जाता है, जो आग का कारण बनता है। कई बस संचालक अतिरिक्त कमाई के चक्कर में यात्रियों की डिक्की या छत पर प्लास्टिक का सामान, केमिकल, या अन्य ज्वलनशील व्यावसायिक पार्सल लाद देते हैं, जो आग को तेजी से भड़काने का काम करते हैं।

यद्यपि आग लगने की घटनाओं से बचाव के यात्रियों और ऑपरेटरों के स्तर पर भी कई उपाय किए गए हैं किंतु प्रश्न यह है कि क्या इन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है? हर बस में कम से कम दो चालू हालत वाले फायर एक्सटिंग्विशर होने अनिवार्य होने चाहिए– एक ड्राइवर के पास और दूसरा आपातकालीन गेट के पास। बसों की सीटों और अंदरूनी हिस्सों में ऐसे फोम और कपड़ों का इस्तेमाल हो जो आग न पकड़ें और जलने पर जहरीला धुआं पैदा न करें (अक्सर लोग आग से कम, जहरीले धुएं से दम घुटने के कारण मरते हैं)। इंजन कंपार्टमेंट में ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम (FDSS) लगाया जाना चाहिए, जो आग लगते ही खुद-ब-खुद उसे बुझा दे। आपातकालीन गेट के पास कोई सीट या सामान नहीं होना चाहिए ताकि वह आसानी से खुल सके। खिड़कियों के शीशे तोड़ने वाले विशेष हथौड़े (Emergency Hammers) हर दो-तीन सीट के बाद लगे होने चाहिए।

शासन और प्रशासन की भी ऐसे मामलों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित की गई है, फिर भी कहीं तो चूक हो ही रही होगी, घटनाएं और उनकी जांच रिपोर्टे तो यही इंगित करती रही हैं। कई बार आरटीओ (RTO) विभाग द्वारा वाहनों की फिटनेस जांच अक्सर केवल कागजों पर या सतही तौर पर होने की आशंका होती है। बसों के भीतर की वायरिंग, इमरजेंसी गेट के काम करने की स्थिति और टायर की गुणवत्ता की बारीकी से शायद जांच में कोई कसर रह जाती है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो प्रशासन दो-चार दिन चेकिंग अभियान चलाकर जुर्माने काटता है और फिर स्थिति वैसी ही हो जाती है। निरंतर कड़ाई का अभाव बस ऑपरेटरों के हौसले बुलंद रखता है। स्लीपर बसों में क्षमता से अधिक केबिन बना दिए जाते हैं, जिससे गैलरी इतनी संकरी हो जाती है कि भगदड़ मचने पर दो लोग एक साथ निकल भी नहीं सकते। कई बार प्रशासन इन अवैध बदलावों को देखकर भी अनदेखा कर देता है। वाहनों के रखरखाव और यात्री बसों के सुरक्षित संचालन के लिए हमारे यहां पर्याप्त नियम और कानून हैं बस उनका ईमानदारी से पालन करने में ही कहीं न कहीं हमसे चूक हो जाती है। बसों की फिटनेस चेकिंग के लिए रैंडम और औचक निरीक्षण होने चाहिए। इसमें सीसीटीवी या डिजिटल ट्रैकिंग का इस्तेमाल हो ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। नियमों का उल्लंघन करने वाले, आपातकालीन गेट न रखने वाले या बस में अवैध कमर्शियल माल ढोने वाले ऑपरेटरों के परमिट तुरंत और स्थायी रूप से रद्द किए जाने चाहिए। सरकार को अनिवार्य नियम बनाना चाहिए कि हर कमर्शियल ड्राइवर और कंडक्टर को 'फायर सेफ्टी और इवेक्यूएशन' (आग लगने पर यात्रियों को निकालने) की बाकायदा ट्रेनिंग मिले और इसका सर्टिफिकेट होने पर ही उन्हें गाड़ी चलाने की अनुमति दी जाए।

और हां! हम यात्रीगण क्या सावधानी रखेंगे? जब भी हम लंबी दूरी या स्लीपर बस से सफर करें, तो सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा आपातकालीन खिड़की और हथौड़ी की स्थिति की जांच पहले ही कर लें। यात्रा के दौरान धूम्रपान न करें और किसी भी ज्वलनशील सामग्री को साथ ले जाने से बचें। जहां तक हो सके अपनी यात्रा के लिए हमेशा मूल कंपनी द्वारा निर्मित या प्रमाणित प्रीमियम बसों (जैसे राज्य परिवहन) को प्राथमिकता दें। बाकी तो शायद हमारे बस में है भी नहीं।

सच तो यह है कि बस संचालकों, शासन, प्रशासन को यात्री सुरक्षा में किसी भी कमी के लिए किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करने की प्रवृत्ति का विकास अपने भीतर करना होगा, तभी बसों में आग लगने की हृदय विदर्क घटनाओं से बचा जा सकेगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

सुधीर देशपांडे

लेखक व्यंग्यकार हैं।

एक सफल साहित्यिक कार्यक्रम के लब्बोलुआब

लब्बोलुआब यह कि जब दस बीस लोग हों तो कार्यक्रम का गरिमामय और महत्वपूर्ण होना भी साबित करता है। तो कोशिश यही होती है कि संख्या कम से कम पाँच और अधिकतम बीस तक तो पहुँचे ही पहुँचे। तब आमंत्रण पत्र को निमंत्रण पत्र बनाने की जद्दोजहद करनी ही पड़ती है। अधिकतर कार्यक्रम चूँकि शाम सात बजे के आसपास ही आयोजित किए जाते हैं, तब यह और अधिक जरूरी हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि पाँच लोग ही कार्यक्रम की धुरी होते हैं। पहला आयोजक, दूसरा संचालक, तीसरा मुख्य अतिथि, चौथा विशिष्ट अतिथि और पाचवाँ कार्यक्रम का अध्यक्ष। श्रोता हो यह भी, छिपी हुई शर्त नहीं है। पर देखा यह जाता है कि ये पाँच भी हुए तो भी किसी कार्यक्रम का कुछ बिगड़ता नहीं है। किसी कार्यक्रम की सफलता में इससे ज्यादा लोगों की उपस्थिति अपेक्षित है भी नहीं। एक कार्यक्रम में तो आयोजक और संचालक की दोनों भूमिकाओं में आयोजक जी ही थे।

किसी भी साहित्यिक आयोजन के केन्द्र में चार पाँच लोगो की भूमिका प्रमुख होती है। यदि ये चार पाँच लोग हैं तो पूरा कार्यक्रम सुफल सम्पन्न हो जाता है. वैसे कार्यक्रम को और सफल करना हो ये चार पाँच लोग भी बढ़कर दस बीस तक पहुँच सकते हैं। लब्बोलुआब यह कि जब दस बीस लोग हों तो कार्यक्रम का गरिमामय और महत्वपूर्ण होना भी साबित करता है। तो कोशिश यही होती है कि संख्या कम से कम पाँच और अधिकतम बीस तक तो पहुँचे ही पहुँचे। तब आमंत्रण पत्र को निमंत्रण पत्र बनाने की जद्दोजहद करनी ही पड़ती है। अधिकतर कार्यक्रम चूँकि शाम सात बजे के आसपास ही आयोजित किए जाते हैं, तब यह और अधिक जरूरी हो जाता है।

तो मैं कह रहा था कि पाँच लोग ही कार्यक्रम की धुरी होते हैं। पहला आयोजक, दूसरा संचालक, तीसरा मुख्य अतिथि, चौथा विशिष्ट अतिथि और पाचवाँ कार्यक्रम का अध्यक्ष। श्रोता हो यह भी, छिपी हुई शर्त नहीं है। पर देखा यह जाता है कि ये पाँच भी हुए तो भी किसी कार्यक्रम का कुछ बिगड़ता नहीं है। किसी कार्यक्रम की सफलता में इससे ज्यादा लोगों की उपस्थिति अपेक्षित है भी नहीं। एक कार्यक्रम में तो आयोजक और संचालक की दोनों भूमिकाओं में आयोजक जी ही थे। जबकि दूसरे कार्यक्रम में आयोजक और अध्यक्षता का दायित्व उनके ही पास था। कुछ मौकों पर ऐसी घटनाएँ होना स्वाभाविक है। वैसे इन साहित्यिक कार्यक्रमों में उपस्थिति बड़ा संकट है, ऐसे मे एक स्वनामधन्य साहित्यकार ने अपने अनुभवों से एक सबक जो लिया उसमें उन्होंने अपने 'निमंत्रण पत्रों' में अतिथियों को चार वर्गों में बाँट दिया। 'अतिथि अपि चतुर्वर्ण भवेत्' की तर्ज पर मुख्य अतिथि, सम्माननीय अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। जब इतने अतिथि आमंत्रित थे, तो न आने का सवाल ही नहीं उठता था। आयोजक जी के अनुसार सुभीता यह था कि सम्माननीय अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट अतिथि एकाधिक हो सकते थे। अब चूंकि मंच पर ही इनकी संख्या बीस से अधिक थी सो मंच के सामने चालीस की उपस्थिति के लिए इन्हीं से आग्रह किया गया था कि इस कार्यक्रम में सपरिवार उपस्थित रहें। इन्हें अपने अतिथियों को सुनने की इच्छा हो या न हो, वे सुनने कम खाने ज्यादा आए थे। कान सुन भले न रहे हों पर उनकी नासिका पकवानों की खुशबू की टोह जरूर लें रही थी। भला तो यह था कि एक अतिथि और अध्यक्ष के अलावा किसी को बोलना नहीं था। चूँकि आयोजक ही संचालन कर रहे थे, तो तीसरे प्राणी वे थे, जो बोल रहे थे। मुख्य अतिथि का भाषण किसी तरह समाप्त हुआ था। इधर संचालक जी ने अध्यक्षीय भाषण हेतु अध्यक्षजी को मंच पर बुलाया तभी, लघुशंका के लिए बाहर गया तेरह चौदह साल का बालक, भीतर आते हुए बोल पड़ा- ' खाना लग गया है। संकेत पाते ही पीछे बैठे लोग धीरे-धीरे बाहर जाने लगे। अध्यक्ष महोदय ने रोकते हुए कहा कि वे ज्यादा देर नहीं बोलेंगे। पर इस बात का कोई असर किसी पर हुआ हो, दिखाई नहीं दिया। होते होते पूरा हाल खाली था। बीस में से वे जिन्हें भाषण नहीं देना था, पर मंच पर विराजमान थे, भोजन के लिए जाने के व्यग्र हो रहे थे। उधर भी खुसुर-फुसुर शुरू हो चुकी थी। सम्माननीय विशिष्ट अतिथि जो पिछली कुर्सियों पर थे भी उठकर जाने लगे। अध्यक्ष जी ने बेमन से अपना भाषण अधूरा ही छोड़ दिया। संचालक जी ने ही आभार व्यक्त किया और सभी से आग्रह किया कि वे भोजन प्राप्त करें। पर वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था, सब पहले ही भोजन पर टूट पड़े थे।

सामयिक

डॉ. रामेश्वर मिश्र

लेखक स्तंभकार हैं।

भोजशाला: इतिहास के आइने में सत्य की खोज

भोजशाला का नाम आते ही भारतीय इतिहास के महान शासक राजा भोज का स्मरण होता है। परमार वंश के इस प्रतापी राजा ने 11वीं शताब्दी में धार को शिक्षा, साहित्य, कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनाया था। राजा भोज केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि महान विद्वान, साहित्यकार और स्थापत्य प्रेमी भी थे। उनके शासनकाल में संस्कृत साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा और वास्तुकला का अभूतपूर्व विकास हुआ। धार नगरी को उस समय विद्या की राजधानी माना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार भोजशाला संस्कृत अध्ययन और देवी सरस्वती की उपासना का प्रमुख केंद्र थी। यह स्थान विद्वानों, कवियों और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का तीर्थ माना जाता था।

भोजशाला भारतीय इतिहास, संस्कृति और आस्था का ऐसा अध्याय है, जिससे समय-समय पर समाज, राजनीति और न्याय व्यवस्था को गहन विमर्श के लिए प्रेरित किया है। मध्य प्रदेश के धार नगर में स्थित यह ऐतिहासिक स्थल केवल पत्थरों और स्थापत्य का समूह नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की स्मृतियों, ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक संघर्षों का जीवंत प्रतीक है। हाल ही में भोजशाला को लेकर आया न्यायालयीय निर्णय एक बार फिर इस विषय को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ले आया है। यह फैसला केवल किसी धार्मिक विवाद का हिस्सा नहीं, बल्कि इतिहास, पुरातत्व, संवैधानिक प्रक्रिया और सामाजिक सौहार्द्र के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी है।

भोजशाला का नाम आते ही भारतीय इतिहास के महान शासक राजा भोज का स्मरण होता है। परमार वंश के इस प्रतापी राजा ने 11वीं शताब्दी में धार को शिक्षा, साहित्य, कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनाया था। राजा भोज केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि महान विद्वान, साहित्यकार और स्थापत्य प्रेमी भी थे। उनके शासनकाल में संस्कृत साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा और वास्तुकला का अभूतपूर्व विकास हुआ। धार नगरी को उस समय विद्या की राजधानी माना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार भोजशाला संस्कृत अध्ययन और देवी सरस्वती की उपासना का प्रमुख केंद्र थी। यह स्थान विद्वानों, कवियों और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का तीर्थ माना जाता था।

भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, कला और विद्या की देवी माना गया है। भोजशाला से जुड़ी अनेक मान्यताएँ इसे माँ वाग्देवी के मंदिर के रूप में प्रस्तुत करती हैं। कहा जाता है कि यहाँ विद्वानों की सभाएं आयोजित होती थीं, शास्त्रार्थ होते थे और विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। यदि हम भारतीय सभ्यता की मूल आत्मा को देखें, तो ज्ञान और शिक्षा को सदैव सर्वोच्च स्थान प्राप्त रहा है। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की परंपरा में भोजशाला को भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखा जाता है।

मध्यकालीन भारत में सत्ता परिवर्तन और आक्रमणों के साथ अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की संरचनाओं में परिवर्तन हुए। भोजशाला भी इस ऐतिहासिक प्रक्रिया से अछूती नहीं रही। बाद के काल में यहाँ कमाल मौला मस्जिद का निर्माण हुआ और यह स्थल दो धार्मिक परंपराओं के साझा इतिहास का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि समय के साथ भोजशाला विवाद का विषय बनती चली गई। हिंदू समाज इसे माँ सरस्वती और राजा भोज की धरोहर मानता रहा, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे मस्जिद के रूप में देखता है। यह विवाद केवल धार्मिक पहचान का प्रश्न नहीं, बल्कि ऐतिहासिक व्याख्या और सांस्कृतिक स्मृति का भी विषय है।

हाल ही में आए फैसले ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा ऐतिहासिक प्रमाणों को गंभीरता से देखने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी ऐतिहासिक विवाद का समाधान भावनाओं या राजनीतिक नारों के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए। यह दृष्टिकोण भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को भी दर्शाता है। न्यायालय ने यह संदेश दिया कि इतिहास की व्याख्या केवल जनभावनाओं से नहीं की जा सकती; इसके लिए निष्पक्ष शोध, पुरातात्विक अध्ययन और प्रमाणिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। भोजशाला विवाद हमें भारतीय इतिहास लेखन की जटिलताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। भारत का इतिहास अनेक परतों से निर्मित हुआ है। यहाँ वैदिक संस्कृति, बौद्ध परंपरा, जैन धर्म, इस्लामी प्रभाव और औपनिवेशिक शासन–सभी ने अपनी छाप छोड़ी है। इसलिए किसी भी ऐतिहासिक स्थल की पहचान केवल एक आयाम में नहीं देखी जा सकती। भोजशाला का प्रश्न भी इसी बहुआयामी इतिहास का हिस्सा है।

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता सह अस्तित्व और समन्वय रही है। यहाँ विविध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएँ सदियों से साथ-साथ विकसित हुई हैं। यदि इतिहास को केवल संघर्ष और टकराव के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, तो समाज में विभाजन बढ़ेगा। किंतु यदि इतिहास को संवाद, समन्वय और सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से देखा जाए, तो वह समाज को जोड़ने का कार्य करेगा। भोजशाला के संदर्भ में भी यही अपेक्षा की जानी चाहिए कि इसे विवाद के बजाय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि भोजशाला को राजनीतिक लाभ और साम्प्रदायिक तनाव का माध्यम बनाने के बजाय शोध और संरक्षण का विषय बनाया जाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इतिहासकारों और सांस्कृतिक संस्थानों को मिलकर इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व पर गहन अध्ययन करना चाहिए। यहाँ उपलब्ध स्थापत्य कला, शिलालेख, मूर्तिकला और अन्य पुरावशेष भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं। यदि इनका व्यवस्थित अध्ययन किया जाए, तो भारतीय मध्यकालीन इतिहास की अनेक अनसुलझी पहेलियों का समाधान संभव हो सकता है। भोजशाला केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय स्थापत्य कला का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ की नक्काशी, स्तंभों की शैली और स्थापत्य संरचना भारतीय कला की समृद्ध परंपरा को दर्शाती है। स्थापत्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थल में परमारकालीन कला के अनेक महत्वपूर्ण तत्व दिखाई देते हैं। यह भारतीय कला इतिहास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इतिहास को किस दृष्टि से देखता है। यदि इतिहास को प्रतिशोध का माध्यम बनाया जाएगा, तो वह संघर्ष को जन्म देगा। किंतु यदि इतिहास को सीख और आत्मबोध का माध्यम माना जाएगा, तो वह समाज को नई दिशा देगा। भोजशाला का प्रश्न हमें यही शिक्षा देता है कि अतीत को समझने के लिए धैर्य, संवेदनशीलता और शोध की आवश्यकता होती है। आज भारत विश्व मंच पर अपनी सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत पहचान को पुर्नस्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे समय में भोजशाला जैसे ऐतिहासिक स्थलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह स्थल भारतीय ज्ञान परंपरा, शिक्षा प्रणाली और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन सकता है। यदि इसे उचित संरक्षण और वैश्विक पहचान मिले, तो यह भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।

भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करता है। इसलिए न्यायालय का दायित्व केवल कानून की व्याख्या करना ही नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी होता है। भोजशाला मामले में भी न्यायपालिका ने इसी संतुलन को स्थापित करने का प्रयास किया है। यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति का प्रमाण है कि यहाँ संवेदनशील मुद्दों का समाधान भी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से खोजा जाता है।

भोजशाला पर आया फैसला समाज के लिए आत्मचिंतन का अवसर भी है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम इतिहास को केवल विवाद और टकराव के रूप में देखना चाहते हैं, या उसे सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का आधार बनाना चाहते हैं। भारत की आत्मा उसकी विविधता और सहिष्णुता में निहित है। यदि हम इन मूल्यों को बनाए रखेंगे, तभी इतिहास का सही अर्थ समझ पाएँगे।

अंततः भोजशाला का प्रश्न केवल एक इमारत या धार्मिक स्थल का प्रश्न नहीं है। यह भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक स्मृति, न्याय व्यवस्था और सामाजिक परिपक्वता की परीक्षा है। इतिहास के आइने में सत्य की खोज तभी संभव है, जब समाज भावनाओं के साथ-साथ तथ्यों और विवेक को भी महत्व दे। भोजशाला पर आया फैसला हमें यही संदेश देता है कि सत्य की खोज संघर्ष से नहीं, बल्कि संवाद, शोध और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से होती है। आज आवश्यकता है कि भोजशाला को भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा के गौरवशाली प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाए। यदि समाज, सरकार और इतिहासकार मिलकर इस दिशा में प्रयास करें, तो भोजशाला आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल एक विवादित स्थल नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की महान विरासत के रूप में जानी जाएगी।

सरोकार

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक एमपी जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत अधिकारी हैं।

आखिर क्यों दिनोंदिन बढ़ रही है अपहरण की घटनाएँ ?

देश में अपहरण और लड़कियों को जबरन उठा ले जाने की घटनाएं पिछले एक दशक में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। हाल ही में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक आईएएस एकेडमी की निदेशक के अपहरण और 1 करोड़ 89 लाख रूपए की फिरौती के मामले ने प्रदेश और देश में सुरक्षा व्यवस्था पर अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि वर्ष 1953 से 2024 तक देश में कुल 20 लाख से अधिक अपहरण के मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें चैंकाने वाला तथ्य यह है कि इन सात दशकों में कुल मामलों का 54 प्रतिशत हिस्सा यानी 11 लाख 24 हजार प्रकरण केवल पिछले एक दशक 2013 से 2024 के दौरान ही दर्ज हुए हैं।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा हाल ही में जारी आँकड़ों के अनुसार पिछले 70 साल में 20 लाख अपहरण के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। किन्तु इसमें चैंकाने वाली बात यह है कि इन आँकड़ों में से 11 लाख अपहरण केवल पिछले 10 सालों में ही बढ़े हैं। यह गंभीर चिंताजनक बात है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार अपहरण की घटनाओं में तीन गुना वृद्धि हुई है। देश में अपहरण और लड़कियों को जबरन उठा ले जाने की घटनाएं पिछले एक दशक में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। हाल ही में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक आईएएस एकेडमी की निदेशक के अपहरण और 1 करोड़ 89 लाख रूपए की फिरौती के मामले ने प्रदेश और देश में सुरक्षा व्यवस्था पर अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि वर्ष 1953 से 2024 तक देश में कुल 20 लाख से अधिक अपहरण के मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें चैंकाने वाला तथ्य यह है कि इन सात दशकों में कुल मामलों का 54 प्रतिशत हिस्सा यानी 11 लाख 24 हजार प्रकरण केवल पिछले एक दशक 2013 से 2024 के दौरान ही दर्ज हुए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल अपराधों में अपहरण की हिस्सेदारी वर्ष 1953 से 1962 के बीच 1.01 प्रतिशत थी। जो 2013 से 2024 के दौरान बढ़कर 3.04 प्रतिशत तक पहुँच गई। अपहरण के कारणों में सबसे बड़ा कारण विवाह के लिए महिलाओं को उठाना और सामान्य अपहरण है। अपहरण के मामलों में राज्यों की तुलना करें तो उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरे नम्बर पर है। वर्ष 2024 के आँकड़ों में बिहार शीर्ष 6 राज्यों में सबसे नीचे दर्ज किया गया है। फिरौती के लिए किए जाने वाले संगठित

अपहरण कुल मामलों का केवल 0.7 प्रतिशत ही है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार पिछले 7 दशकों में से प्रत्येक दशक में अपहरण और उसकी हिस्सेदारी इस प्रकार है - सन् 1953 से 1962 के बीच 60,463 अपहरण हुए थे। कुल अपहरण में इसकी हिस्सेदारी 1.01 प्रतिशत ही थी। 1963 से 1972 के दशक में कुल 85,401 हुए। कुल अपहरण में इसकी हिस्सेदारी भी 1.01 प्रतिशत ही थी। 1973 से 1982 तक के दशक में 1,22,905 अपहरण हुए। कुल अपहरण में इसकी हिस्सेदारी 0.98 प्रतिशत थी।

सन् 1983 से 1992 के दशक में कुल अपहरण 1,68,112 अपहरण हुए। कुल अपहरण में इसकी हिस्सेदारी 1.13 प्रतिशत थी। सन् 1993 से 2002 के दशक में कुल अपहरण 2,17,949 हुए। कुल अपहरण में इसकी हिस्सेदारी 1.26 प्रतिशत थी। सन् 2003 से 2012 तक के दशक में कुल अपहरण 3,05,438 हुए। कुल अपहरण में इसकी हिस्सेदारी 1.33 प्रतिशत थी। सन् 2013 से 2024 के दौरान अपहरण की संख्या में अचानक तीन गुना वृद्धि हो गई! इस दशक में कुल अपहरण 11,24,117 हुए। कुल अपहरण में इसकी हिस्सेदारी 3.04 प्रतिशत थी। ये आँकड़ें भयावह और चैंकाने वाले हैं। दिनोंदिन अपहरण की बढ़ती हुई संख्या चैंकाने वाली है। साथ ही आश्चर्यजनक भी है। जिस परिवार में किसी लड़की या लड़के का अपहरण होता है तो उस पर क्या गुजरती है, यह वहीं जानता है। पूरे परिवार की नींद उड़ जाती है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इन आँकड़ों को गंभीरतापूर्वक लें और योजनाबद्ध तरीके से अपहरण के बच्चे को न केवल ढूँढ निकाले, बल्कि भविष्य में अपहरण नहीं होने पाए, इसके लिए कठोर नियम बनावें, ताकि कोई किसी परिवार के दिन का चेन और रात की नींद खराब नहीं होने पाए।

मुद्दा

अरुण कुमार डनायक

लेखक भारतीय स्टेट बैंक सेवानिवृत सहायक महाप्रबंधक हैं।

आर्थिक संयम की अपील: राष्ट्रवाद या संकट प्रबंधन?

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से आपूर्ति श्रृंखलाएँ और तेल कीमतें प्रभावित हैं; ऐसे में 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए विदेश यात्रा व सोने की खरीद टालने, पेट्रोलडीज़ल की खपत घटाने, सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने तथा जीवनशैली में बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने पार्सल ढुलाई को रेल से और वर्कफ्रॉमहोम को प्रोत्साहित करने की भी सलाह दी। यह अपील सतही तौर पर 'आर्थिक राष्ट्रवाद' लगती है, पर संदर्भ में यह वैश्विक अस्थिरता और घरेलू दबावों की आपात प्रतिक्रिया प्रतीत होती है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने भारत जैसे आयात-निर्भर देश पर दबाव बढ़ाया है। इसी पृष्ठभूमि में रुपया 95 प्रति डॉलर के पार पहुँचा–जो बाह्य क्षेत्र पर बढ़ते दबाव का संकेत है, जहाँ हाल के महीनों में निर्यात-आयात असंतुलन से बढ़ता चालू खाता घाटा और उससे भी अधिक पूंजीगत खाते की कमजोरी–विशेषकर विदेशी निवेश, बाहरी उधारी और अन्य पूंजी प्रवाह में कमी–रुपये पर दबाव के प्रमुख कारण रहे हैं।

ऊर्जा और सोने पर भारी आयात निर्भरता भारत की संरचनात्मक कमजोरी रही है । तेल और सोने की ऊँची कीमतें डॉलर की मांग बढ़ाती हैं। खाड़ी देशों से प्रेषण पर अनिश्चितता ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। इस दबाव के बीच तेल वितरण कंपनियों को लगभग रू. 1000 करोड़ का घाटा प्रतिदिन हो रहा है और खरीफ सीजन से पहले उर्वरकों के कच्चे माल जैसे प्राकृतिक गैस, पोटाश, अमोनिया जैसे रसायनों का महँगा आयात भी अपरिहार्य है। रासायनिक उर्वरकों की कमी या महँगाई से कृषि उत्पादन प्रभावित होने और खाद्य कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका है, जो समय रहते नियंत्रण न होने पर खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती बन जायेगी । ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील मूलतः डॉलर की मांग घटाने का एक 'आसान विकल्प' भर है, जबकि परिस्थितियाँ कीमतों के यथार्थपरक समायोजन जैसे कठिन, पर अधिक प्रभावी, निर्णयों की मांग करती हैं। व्यवहारिक स्तर पर भी इस अपील की सीमाएँ स्पष्ट हैं। अधिकांश शहरों में सार्वजनिक परिवहन अव्यवस्थित, भीड़भाड़ वाला और समय-साध्य है। दूसरी ओर, राजनीतिक रैलियों, सरकारी काफिलों और आयोजनों में संसाधनों का व्यापक उपयोग 'कथनी और करनी' के अंतर को उजागर करता है। मध्यप्रदेश में निगम-मंडल अध्यक्षों का सैकड़ों वाहनों के साथ राजधानी भोपाल पदभार ग्रहण करने पहुँचना इस विरोधाभास को और गहरा करता है। यह विरोधाभास जनता से अपेक्षित संयम की नैतिक ताकत को कमजोर करता है। बाज़ार की प्रतिक्रिया ने इस अपील के निहितार्थ को और स्पष्ट किया। एविएशन, पर्यटन और ज्वेलरी क्षेत्रों में तेज़ गिरावट आई और एक ही दिन में लगभग रू. 4 लाख करोड़ की बाज़ार पूंजीकरण में कमी दर्ज की गई। पेट्रोल कीमत में हालिया बढ़ोतरी ने निवेशकों की आशंका को पुष्ट कर दिया है, जबकि बढ़ते आर्थिक दबाव के कारण समग्र आर्थिक संतुलन बिगड़ने

की संभावना भी बनी हुई है।

सरकार ने 69 दिनों के कच्चे तेल, एलएनजी और 45 दिनों के एलपीजी भंडार का हवाला देकर स्थिति को नियंत्रित बताया है, लेकिन दीर्घकालिक संकट की स्थिति में यह पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इससे ऊर्जा नीति की सीमाएँ भी उजागर होती हैं । सौर, पवन और भंडारण जैसी वैकल्पिक ऊर्जा में निवेश की गति धीमी है और इलेक्ट्रिक वाहनों, इंडक्शन कुकिंग तथा बायोगैस जैसे विकल्पों का विस्तार सीमित है। पेट्रोलियम भंडारण क्षमता भी पिछले एक दशक से नहीं बढ़ी है। 2003 में शुरू हुई रणनीतिक भंडारण परियोजना का दूसरा चरण–जिसे 2021 में मंजूरी मिली–बजट और प्रक्रियागत देरी के कारण अब तक ज़मीन पर नहीं उतर सका है, परिणामस्वरूप पेट्रोलियम पर निर्भरता कम नहीं हो पाई है।

नोटबंदी और कोविड लॉकडाउन की तरह इस बार भी अपील के बाद स्थिति स्पष्ट करने के लिए मंत्रियों को सामने आना पड़ा, जो संकेत देता है कि निर्णय और उसके प्रभावों के आकलन के बीच संतुलन अक्सर कमजोर रहता है। भारत की विदेश नीति के क्रियान्वयन पर भी प्रश्न उठते हैं। संकट की इस संवेदनशील घड़ी में शीर्ष स्तर की पश्चिम एशिया यात्राओं का समय और प्राथमिकता स्पष्ट रणनीतिक संदेश नहीं दे पातीं। बढ़ते तनाव के बीच ऐसी सक्रियता कूटनीतिक पहल तो दिखाती है, पर उसके ठोस परिणामों और रणनीतिक लाभों पर पारदर्शिता का अभाव बना रहता है।

सबसे गंभीर प्रश्न संसदीय लोकतंत्र और संसद में जवाबदेही से जुड़ा है । इतने महत्वपूर्ण वैश्विक संकट पर संसद में व्यापक चर्चा और सर्वसम्मत नीति-निर्माण अपेक्षित था, लेकिन सरकार की सक्रिय पहल का अभाव दिखा। विपक्ष के सुझावों की अनदेखी और संवाद की कमी से संकट प्रबंधन संस्थागत विमर्श के बजाय सीमित दायरे में सिमटता प्रतीत होता है। सांस्कृतिक पहल के नाम पर मंदिरों में स्वर्णमंडन की भव्य परियोजनाओं के बीच सोना न खरीदने की अपील एक विरोधाभास पैदा करती है। एक ओर आर्थिक संयम का संदेश है, तो दूसरी ओर स्वर्ण उपयोग का विस्तार 'स्वर्ण संसाधन अवरोध' को बढ़ावा देता दिखता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक भी हाल के वर्षों में अपने स्वर्ण भंडार में लगातार वृद्धि कर रहा है। मार्च 2026 तक बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 16.7% हो गई, जो छह महीने पहले 13.92% थी। वैश्विक स्तर पर कई केंद्रीय बैंक आर्थिक अनिश्चितता और बाजार अस्थिरता से बचाव के लिए सोना एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में बढ़ा रहे हैं, जो संस्थागत स्तर पर इसके महत्व को दर्शाता है। हालांकि सोना खरीदना व्यक्तिगत रूप से गलत नहीं है, पर यह केवल निजी पसंद नहीं, बल्कि भारत की पारंपरिक बचत प्रवृत्ति और आधुनिक आर्थिक आवश्यकताओं के बीच एक संरचनात्मक द्वंद्व भी है। ऐसे में नीति-निर्माण के स्तर पर इन दोनों प्रवृत्तियों के बीच अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता महसूस होती है। यद्यपि भारत के पास लगभग 690 बिलियन डॉलर का पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर) का आपात उपयोग भी नहीं करना पड़ा है, इसलिए 1990-91 जैसी गंभीर स्थिति की आशंका फिलहाल कम है; तथापि विलंब से उठाए गए कदमों के बीच ऐसी अपील आर्थिक रूप से उचित प्रतीत होती है, पर इसकी प्रभावशीलता सरकार की नीतिगत सुसंगति और विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। यदि समय रहते ऊर्जा विविधीकरण, आयात निर्भरता में कमी और संस्थागत संवाद मजबूत किए गए होते–साथ ही अस्थिर विदेशी संस्थागत व पोर्टफोलियो निवेश को आकर्षित करने वाली नीतियाँ सुधारी जातीं, गोल्ड बॉन्ड अधिक आकर्षक बनाए जाते, संकटसंचार पेशेवर होता और पेट्रोलियम भंडारण विस्तार समय पर होता–तो आज स्थिति इतनी दबावपूर्ण न होती। आर्थिक संकट से निपटने के लिए केवल जनता से संयम की अपेक्षा पर्याप्त नहीं–सरकार भी अपने निर्णयों, प्राथमिकताओं और आचरण में आवश्यक पारदर्शिता दिखाए, तभी 'आर्थिक राष्ट्रवाद' ठोस राष्ट्रीय प्रयास बन पाएगा।

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया
लेखक स्तंभकार हैं।

ओटीटी, रियलिटी शो : युवाओं की सफलता के बदलते मापदण्ड

समय के साथ समाज की सोच, जीवन-शैली और सफलता के अर्थ निरन्तर परिवर्तित होते रहे हैं। कभी सफलता का अर्थ ज्ञान, संस्कार, धैर्य और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना माना जाता था, किन्तु आज तकनीक और मनोरंजन की चकाचौंध ने सफलता की परिभाषा को एक नए रूप में प्रस्तुत कर दिया है। विशेष रूप से ओटीटी मंचों और रियलिटी शो ने युवाओं की सोच, आकांक्षाओं और जीवन-दृष्टि को गहराई से प्रभावित किया है। आज का युवा केवल परिश्रम और धैर्य से मिलने वाली उपलब्धियों की ओर ही आकर्षित नहीं है, बल्कि वह त्वरित प्रसिद्धि, लोकप्रियता और बाहरी चमक को भी सफलता का प्रतीक मानने लगा है।

ओटीटी मंचों ने मनोरंजन की दुनिया को एक नया आयाम दिया है। अब दर्शक केवल दूरदर्शन या सिनेमाघरों तक सीमित नहीं रहे। मोबाइल और इंटरनेट ने मनोरंजन को हर व्यक्ति की पहुँच में ला दिया है। विविध विषयों पर आधारित वेब-श्रृंखलाएँ, फिल्मों की नवीन प्रस्तुति और स्वतंत्र अभिव्यक्ति ने युवाओं को आकर्षित किया है। ओटीटी ने अनेक कलाकारों को अवसर प्रदान किए, समाज के उपेक्षित विषयों को मंच दिया और रचनात्मकता को नई दिशा भी प्रदान की। यह आधुनिक तकनीक का एक सकारात्मक पक्ष है।

किन्तु इसके साथ ही एक गम्भीर प्रश्न भी उभरकर सामने आया है–क्या लोकप्रियता ही सफलता का वास्तविक मापदण्ड बन चुकी है? आज सोशल मीडिया पर अनुयायियों की संख्या, कैमरे के सामने दिखाई देने वाली भव्यता और क्षणिक प्रसिद्धि को सफलता का पर्याय माना जाने लगा है। अनेक युवा यह मानने लगे हैं कि जीवन में संघर्ष, अध्ययन और धैर्य से अधिक महत्त्व त्वरित पहचान का है। यही मानसिकता उन्हें रियलिटी शो की ओर आकर्षित करती है।

रियलिटी शो आज केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गए, बल्कि वे युवाओं के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली मंच बन चुके हैं। गायन, नृत्य, अभिनय अथवा साहसिक प्रतियोगिताओं पर आधारित ये कार्यक्रम युवाओं को प्रसिद्धि पाने का अवसर देते हैं। कई प्रतिभाशाली युवाओं ने इन मंचों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है और अपने जीवन को नई दिशा दी है। यह इन कार्यक्रमों का सकारात्मक पक्ष है कि वे छिपी हुई प्रतिभाओं को समाज के सामने लाते हैं।

परन्तु दूसरी ओर इन कार्यक्रमों में प्रतिस्पर्धा की तीव्रता, कृत्रिम भावनात्मक प्रस्तुतियाँ और लोकप्रियता प्राप्त करने की होड़ कई बार युवाओं के मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है। कैमरे के सामने निर्मित कृत्रिम जीवन उन्हें यह विश्वास दिलाने लगता है कि सफलता केवल प्रसिद्ध हो जाने में है। परिश्रम की गहराई, ज्ञान का मूल्य और नैतिकता की गरिमा धीरे-धीरे पीछे छूटती दिखाई देती है। आज अनेक युवा अपने व्यक्तित्व का निर्माण वास्तविक जीवन के आदर्शों से नहीं, बल्कि आभासी मंचों के प्रभाव से करने लगे हैं।

यही कारण है कि समाज में सफलता के मापदण्ड भी परिवर्तित होते दिखाई दे रहे हैं। पहले किसी व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र, व्यवहार और ज्ञान से होती थी, जबकि आज उसकी पहचान उसके बाहरी प्रदर्शन और सामाजिक माध्यमों पर सक्रियता से आँकी जाने लगी है। यह परिवर्तन केवल सामाजिक नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। युवा पीढ़ी धैर्य की अपेक्षा शीघ्र उपलब्धि चाहती है और यही अधैर्य उन्हें अनेक बार निराशा की ओर भी ले जाता है।

फिर भी यह कहना उचित नहीं होगा कि ओटीटी और रियलिटी शो पूर्णतः नकारात्मक हैं। वास्तव में समस्या माध्यमों में नहीं, बल्कि उन्हें देखने और समझने की दृष्टि में है। यदि युवा इन मंचों को प्रेरणा, ज्ञान और रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में ग्रहण करें, तो वे उनके व्यक्तित्व-विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अनेक वेब-श्रृंखलाएँ सामाजिक समस्याओं, ऐतिहासिक घटनाओं और मानवीय संवेदनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं। इसी प्रकार कई रियलिटी शो प्रतिभा और परिश्रम के महत्त्व को भी स्थापित करते हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि युवा सफलता के वास्तविक अर्थ को समझें। सफलता केवल प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आत्मसन्तोष, नैतिक मूल्यों और समाज के प्रति उत्तरदायित्व से भी जुड़ी होती है। जो उपलब्धि व्यक्ति को भीतर से रिक्त कर दे, वह स्थायी सफलता नहीं हो सकती। जीवन का वास्तविक सौन्दर्य बाहरी चमक में नहीं, बल्कि व्यक्तित्व की गहराई में निहित होता है।

अन्ततः ओटीटी और रियलिटी शो आधुनिक युग की ऐसी वास्तविकताएँ हैं, जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने समाज को नए अवसर दिए हैं, परन्तु साथ ही सफलता के मापदण्डों को भी बदल दिया है। आज आवश्यकता इस संतुलन की है कि युवा आधुनिक माध्यमों का उपयोग करें, परन्तु अपनी संवेदनाओं, संस्कारों और जीवन-मूल्यों को विस्मृत न करें। जब आधुनिकता और विवेक साथ चलते हैं, तभी सफलता केवल क्षणिक प्रसिद्धि नहीं, बल्कि जीवन की सार्थक उपलब्धि बन पाती है।

एसडीएम ने पिताश्री की स्मृति में कराया जरूरतमंदों को भोजन

सोहागपुर। अनुविभागीय अधिकारी सुश्री प्रियंका भल्लावी ने विगत माहों पर आपने पिताश्री स्वर्गीय श्री दीपक भल्लावी की स्मृति में राम रहीम रोटी बैंक समिति के माध्यम से रेल्वे स्टेशन परिसर में जरूरतमंदों मातृशक्ति एवं जरूरतमंद नागरिकों को अपने यहां से बनवाकर लाए गए भोजन को वितरित किया गया। सुश्री प्रियंका भल्लावी ने इसे यादगार बनाने के उद्देश्य से अपने हाथों से परोसकर जरूरतमंद बेघर बेसहारा लोगों को भरपूर स्वादिष्ट भोजन कराया । इस कार्य में उनकी सहयोगी माताश्री अनुमति भल्लावी,भाई सुमित भल्लावी एवं अमित भल्लावी एवं अनुराग तिवारी बने। उन्होंने भी इस पुण्य अवसर सहयोग गया। उल्लेखनीय है कि विगत वर्षो से राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर रेल्वे स्टेशन परिसर में

जरूरतमंदों को भोजन करवाती है। ज्ञातव्य है कि राम रहीम रोटी बैंक इतना प्रसिद्धि प्राप्त हो गया है। नगर ही आस-पास के ग्रामीण जन भी पुण्य तिथि, जन्मदिन एवं अन्य शुभ कार्यों में नागरिक भोजन करवातें है। एसडीएम प्रियंका भल्लावी के उक्त कार्य पर राम रहीम रोटी बैंक के पदाधिकारियों ने प्रशंसा की है।

श्रद्धांजलि सभा – युवा कांग्रेस नेता पूर्व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं वकील कार्तिक शर्मा के पिताजी विजयकुमार शर्मा का लंबी बीमारी के बाद देवलोक भवन हो गया। उनके निधन उपरांत राज ग्रार्डन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया । इस श्रद्धांजलि सभा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पुष्पराजसिंह पटेल, पूर्व नपाध्यक्ष संतोष मालवीय, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सुधीर ठाकुर,नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल, वकील मंगलसिंह रघुवंशी, राजकुमार रघुवंशी, वकील संजय तिवारी, देवान्शु शर्मा पार्षद भास्कर मांझी, पूर्व पार्षद मोहन कहार, वकील नीरज शर्मा,उमेश रघुवंशी आदि उपस्थित थे।

ट्रेक्टर ट्राली ने मारी टक्कर – सोहागपुर के समीपवर्ती ग्राम रेवा बनखेड़ी में विगत दिवस रेत चोरी की ट्रेक्टर ट्राली ने करीबन तीन बाइक को टक्कर मार दी। बताया जाता है कि इन रेत चोरों के होसले इतने बुलंद हैं कि कोई उनके खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने से डरते हैं। उल्लेखनीय है कि रेवा बनखेड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। इसलिए रेत की कोई कमी नहीं है। वहीं पता चला है कि बरसात में भी ग्राम के समीप रेत बहकर आती है। इस कारण बेखोफ रेत का दोहन होता है। पता चला है तीन बाइक वालों अपनी-अपनी बाइक खुद सुधरवा रहें हैं।

प्रभारी मंत्री मंगलवार को जनसुनवाई में होंगे शामिल, जनसमस्याओं का करेंगे समाधान

बैतूल। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल मंगलवार को बैतूल आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रभारी मंत्री श्री पटेल ट्रेन द्वारा दोपहर 12 बजे रेलवे स्टेशन बैतूल पहुंचेंगे। इसके पश्चात वे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में सम्मिलित होकर आमजन की समस्याएं सुनेंगे तथा समस्याओं का समाधान करेंगे। कार्यक्रम उपरांत प्रभारी मंत्री श्री पटेल शाम 5.25 बजे ट्रेन द्वारा बैतूल रेलवे स्टेशन से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।

तीसरी रेलवे लाइन निर्माण में अवैध खनिज भंडारण पर 36 लाख 95 हजार का जुर्माना

बैतूल। आमला तहसील के ग्राम हसलपुर में तीसरी रेलवे लाइन निर्माण कार्य के दौरान बिना अनुमति रेत एवं गिट्टी का भंडारण करने के मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय बैतूल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित कंपनियों पर 36 लाख 95 हजार 400 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।

प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से उप संचालक खनि प्रशासन बैतूल द्वारा प्रस्तुत मामले में बताया कि प्रकाशित समाचार 'तीसरी रेलवे लाइन के काम के लिए प्लांट लगाने नहीं ली किसी भी प्रकार की अनुमति' के आधार पर सहायक खनि अधिकारी बैतूल ने 8 मई 2025 को हल्का पटवारी के साथ मौजा हसलपुर, तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 201 का निरीक्षण किया था।

निरीक्षण के दौरान रेलवे लाइन किनारे स्थापित आरएमसी प्लांट के आसपास गिट्टी, डस्ट और रेत के बड़े-बड़े ढेर पाए गए। नापजोख में 257 घनमीटर गिट्टी/डस्ट तथा 246 घनमीटर रेत का भंडारण मिला। मौके पर मौजूद प्लांट ऑपरेटर मनीष यादव ने बताया कि प्लांट मेसर्स वायएसएम बिल्डकॉन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का है, जो केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए रेलवे की तीसरी लाइन निर्माण कार्य में कांक्रीट सप्लाई का कार्य कर रही थी। जांच के दौरान खनिजों की रॉयल्टी रसीद और भंडारण अनुमति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए। इसके बाद सहायक खनि अधिकारी ने पंचनामा तैयार कर खनिज सामग्री जब्त कर सुरक्षार्थ सुपुर्दगी में दी तथा प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि अनावेदक कंपनियों द्वारा बिना वैध अनुज्ञा के खनिज भंडारण किया गया, जो मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 का उल्लंघन है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि शासकीय निर्माण कार्यों में भी बिना वैध खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति के गौण खनिजों का उपयोग या भंडारण नहीं किया जा सकता। अपर कलेक्टर वंदना जाट ने आदेश पारित करते हुए मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के नियम 18(6) के तहत मेसर्स वायएसएम बिल्डकॉन कंपनी प्रा. लि. एवं केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड पर कुल 36 लाख 95 हजार 400 रुपये की शास्ति अधिरोपित की। साथ ही उप संचालक खनि प्रशासन बैतूल को नियम 22 के तहत शास्ति राशि की वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं।

सोनाघाटी में अवैध मुरूम उत्खनन पर 32 लाख 25 हजार का जुर्माना, पोकलेन मशीन राजसात

जिले के सोनाघाटी क्षेत्र में अवैध मुरूम उत्खनन के मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय बैतूल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी पर 32 लाख 25 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। साथ ही उत्खनन में प्रयुक्त पोकलेन मशीन को शासन के पक्ष में अधिहरित करने के आदेश भी दिए गए हैं। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से उप संचालक खनि प्रशासन बैतूल द्वारा प्रस्तुत मामले में बताया कि 15 जनवरी 2025 की रात लगभग 2:30 बजे थाना कोतवाली बैतूल पुलिस को मौजा सोनाघाटी स्थित खसरा नंबर 105/5 पर अवैध मुरूम उत्खनन की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां एक चेन माउंटेड पोकलेन मशीन से मुरूम उत्खनन करते हुए पाया गया। पुलिस जब मशीन को थाना ले जा रही थी, उसी दौरान दो खाली डम्पर क्रमांक एमपी 48 एच 5560 एवं एमएच 27 एक्स 0801 उत्खनन स्थल की ओर जाते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों वाहन चालक डम्पर छोड़कर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने दोनों डम्परों को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कराया। अगले दिन सहायक खनि अधिकारी बैतूल एवं विभागीय अमले द्वारा स्थल निरीक्षण कर गड्ढों की नपाई की गई, जिसमें कुल 3465 घनमीटर मुरूम उत्खनन होना पाया गया। जांच के दौरान पोकलेन ऑपरेटर अज्जू फरकाड़े ने अपने बयान में बताया कि मशीन शेख निजाम निवासी टिकारी की है और उनके कहने पर रात में मुरूम निकालकर डम्परों से परिवहन किया जाता था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि अनावेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित है। हालांकि दोनों डम्परों को खाली अवस्था में जब्त किए जाने के कारण अवैध परिवहन में उनकी संलिप्तता प्रमाणित नहीं मानी गई। अपर कलेक्टर वंदना जाट ने आदेश पारित करते हुए मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के नियम 18(6) के तहत शेख निजाम पर 32 लाख 25 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की।

ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में जिलेभर के मेडिकल स्टोर कल बंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे जिले के दवा विक्रेता

बैतूल। ऑनलाइन फार्मेसी और कॉरपोरेट कंपनियों की कथित मनमानी के विरोध में 20 मई को बैतूल जिले की 800 से अधिक दवा दुकानें बंद रहेंगी। बंद के दौरान बैतूल जिले के दवा विक्रेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन में अवैध ऑनलाइन फार्मेसी पर तत्काल हस्तक्षेप करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) के राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान को जिला औषधि विक्रेता संघ बैतूल ने पूर्ण समर्थन देते हुए जिले के सभी मेडिकल संचालकों से बंद को सफल बनाने की अपील की है। दवा विक्रेताओं ने फर्जी ई-प्रिस्क्रिप्शन, अनियंत्रित होम डिलीवरी और कॉरपोरेट कंपनियों की अत्यधिक छूट को जनस्वास्थ्य व छोटे व्यापारियों के लिए गंभीर खतरा बताया है। संगठन ने केंद्र सरकार से मरीजों की सुरक्षा और दवा वितरण व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। जिला औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष मनजीत सिंह साहनी, सचिव सुनील सलूजा एवं कोषाध्यक्ष जयदेव गायकी ने बताया कि यह बंद ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ किया जा रहा है, जो नियमों की कमजोरियों का फायदा उठाकर दवाओं की बिक्री कर रहे हैं। संगठन का आरोप है कि इससे न केवल छोटे दवा व्यापारियों का अस्तित्व संकट में है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पर्याप्त सत्यापन दवाओं की बिक्री, एक ही प्रिस्क्रिप्शन का बार-बार उपयोग तथा भारी छूट देकर बाजार व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है। इससे जिले सहित ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में छोटे मेडिकल स्टोर्स पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत बैतूल जिले की 800 से अधिक दवा दुकानें 20 मई को पूरी तरह बंद रहेंगी। इस दौरान मेडिकल संचालक केंद्र सरकार से ई-फार्मेसी पर सख्त नियंत्रण, अनुचित छूट पर रोक तथा दवा विक्रेताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग को लेकर एकजुटता प्रदर्शित करेंगे।

अपने जीवन में एक बार अवश्य ही गौ दान करें, कलयुग का अंत निकट है, जपे माधव, माधव जगन्नाथ संस्कृति के विद्वान श्री मिश्र उड़ीसा

भोपाल। समस्त देवी-देवताओं को नमन एवं माधव माधव कहते जगन्नाथ संस्कृति के विशारद विद्वान पंडित डॉ काशीनाथ मिश्र उड़ीसा ने भोपाल गर्ल्स स्कूल पंचवटी परिसर के खचाखच भरे परिसर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा, भविष्य मालिका पुराण की कथा के प्रारंभ में कहा कि अपने जीवन में एक बार अवश्य ही गौ माता का दान करें। यह छोटी-सी बात नहीं वरन् यह आपके मृत्यु के बाद आपको तारने वाली अकाट्य सत्य बात है। आपने कहा कि नर्क के 22 लोक है। वहीं बैकुंठ के साथ लोक 7लोक बतलाएं गए हैं। भूलोक - हमारी पृथ्वी जहाँ मनुष्य रहते हैं भुवर्लोक - पृथ्वी और सूर्य के बीच का अंतरिक्ष जहाँ ग्रह-नक्षत्र हैं। स्वर्गलोक - इंद्रदेव का स्वर्ग जहाँ देवता और पुण्य आत्माएं रहती हैं। महर्लोक - ऋषियों और मुनियों का निवास स्थान। जनलोक - ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनत कुमारों का लोक।तपोलोक परम तपस्वियों और सिद्ध पुरुषों का लोक। सत्यलोक (ब्रह्मलोक) - सर्वोच्च लोक, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं।आपने एक प्रसंग के माध्यम से समझाया कि उड़ीसा के एक ग्राम एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई।उस समय एक 50 साल की महिला की भी मृत्यु हुई। नर्क में जाना बहुत ही दुःख दाई है। जब दोनों को यमलोक पहुंचे तो उन्हें पूछा गया कि आपने गौ दान किया है। तब वह युवक गौ की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पर कर गया। किन्तु उस महिला ने गौ दान नहीं किया था। वहीं महिला की मृत्यु का समय पूरा नहीं हुआ था।तब उसे पुनः वापिस भेजा दिया गया। यह उड़ीसा के गांव की कहनी है। उसने वहां का बात सुनाई।श्री मिश्र जी ने कहा कि वैतरणी पार न करने पर 50 हजार साल तक नर्क भोगना पड़ता है। नर्क में जाना बहुत

दुःख का कारण है। मैं सब के कल्याण की बात कहता हूं कि यह वैभव नहीं रहेगा। लेकिन भगवत् नाम माधव माधव नाम ही सब कष्ट को दूर करेगा। आपने आगे बताया कि मृत्यु होने के तीन महीने पूर्व ही संकेत आता जाता है। तब हमें दान, पुण्य करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सब दे दो। थोड़ा थोड़ा पैसा अन्न दान ही बड़े बड़े पातकों को दूर कर देता है। जैसे पुत्र पिता की सेवा करें पति पत्नी,या पत्नी पति,बहु,सास की सेवा करें।श्री मिश्र जी ने अच्युतानंद एवं राजा तत्वाग का उत्कृष्ट प्रसंग सुनाते कहा कि देवता की तरफ से लड़ते-लड़ते उनकी मृत्यु का समय आया उनको बताया गया कि उनकी मृत्यु में दो घड़ी का समय है। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त पवित्र नदी में स्नान करके वैकुंठ प्राप्त किया।कर्म कभी निरर्थक नहीं जाता। आपने सुकदेव एवं राजा परीक्षित का भी प्रसंग को समझाया।नवादा बस्ती में पूजा-अर्चना के बाद नृत्य करते हैं तभी पूजा अर्चना सार्थक होती है। भक्तों के साथ बैठना। भगवत कथा श्रवण करना बन्धु बनाओ।

डॉ काशीनाथ मिश्र ने कहा कि वर्तमान को जो परिस्थितियां विद्यमान हैं उससे यह अब कलयुग का अंत निकट है। आपने इसके उदाहरण देते मानवीय आचरण, मातृशक्ति के हरण, कन्या हरण,गौ हत्या, एवं कई आज के चाल-चलन पर कटाक्ष किए। सब जाति एक के कारण वर्णशकर का आगमन,उत्पत्ति होना आदि मानवीय विकृति इसके प्रमाण करते ध्यानाकर्षण कराया। वर्तमान में मानव जीवन का उद्धार कैसे होगा। भक्ति एवं मुक्ति मार्ग क्या है। आपने भविष्य मालिका पुराण का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जो पुराने ग्रुथ हैं ये मिथ्या नहीं हो सकते। आपने पूर्व राजनेताओं आदि के उदाहरण देकर कहां कि भारत में महिला राष्ट्रपति बनेगी। भारत चन्द्र पर राकेट भेजेगा। भारत एक नम्बर है । एक नंबर बनेगा। आपने चेताया कि वर्तमान वायरस अफ्रीका में आ गया है। यूरोपीय देशों के यहां भी आएगा। तृतीय विश्व युद्ध की भी आपने चेतावनी दी है। डॉ काशीनाथ मिश्र जी उड़ीसा कहते हैं कि भक्ति एवं मुक्ति का मार्ग माधव माधव है। मनुष्य को अपनी जीवनशैली में त्रिकाल संध्या का पाठ अवश्य करना चाहिए। यही असंभव को संभव बनाएगा। इसी अवसर पर पंचवटी कालोनी एवं इन्द्र विहार कालोनी से नौ कन्याएं मुख्य आर्कषण का केन्द्र रही। खूबचदानी परिवार द्वारा प्रदत्त सामग्री डाः काशीनाथ मिश्र ने कन्याओं को प्रदान की। इसके पूर्व विधायक भगवानदास सबनानी ने श्री मिश्र जी का शाल एवं फूलमालाओं से स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर राधावल्लभ पाठक, विनोद महराज बाबू, शिवराज तलरेजा आयोजन श्रीमती नीरजा गोलानी खूबचदानी, पंकज खूबचदानी,सतरामदास खूबचदानी, जे डी गोलानी सोहागपुर सहित भारी संख्या में मातृशक्ति एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कथा में केशव माधव हरि हरि बोल, गोविंद माधव,राम नाम हीरे मोती, मैं गाऊं गाऊ गली गली आदि गीत पर श्रद्धालुओं ने नृत्य किए। कार्यक्रम के बाद खूबचदानी परिवार ने अंत प्रसाद वितरण किया।

प्रभारी मंत्री मंगलवार को जनसुनवाई में होंगे शामिल, जनसमस्याओं का करेंगे समाधान

बैतूल। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल मंगलवार को बैतूल आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रभारी मंत्री श्री पटेल ट्रेन द्वारा दोपहर 12 बजे रेलवे स्टेशन बैतूल पहुंचेंगे। इसके पश्चात वे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में सम्मिलित होकर आमजन की समस्याएं सुनेंगे तथा समस्याओं का समाधान करेंगे। कार्यक्रम उपरांत प्रभारी मंत्री श्री पटेल शाम 5.25 बजे ट्रेन द्वारा बैतूल रेलवे स्टेशन से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।

एमपी में 48 घंटे में भरने होंगे सड़कों के गड्ढे

भोपाल (नप्र)। सड़क पर बने गड्ढों, खुले नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों में अब प्रशासन और सड़क निर्माण एजेंसियों को बैरिकेडिंग करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर 48 घंटे के भीतर गड्ढे भरने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है।

मुख्य सचिव को भेजे पत्र में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी ने दो महीने में रिपोर्ट मांगी है। बारिश में ऐसे स्थानों पर रात में प्रकाश व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि सड़क हादसे न हों।

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी ने बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। समिति ने गड्ढों, खुले नालों, मैनहोल और बिना बैरिकेड वाले जलभराव क्षेत्रों की तुरंत मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भी इस संबंध में निर्देश जारी कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। समिति ने पत्र में कहा है कि सड़क किनारे खुले और बिना रोशनी वाले जलभराव क्षेत्र तथा खराब सड़कें जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण बन रही हैं। सड़क सुरक्षा में लापरवाही से कई लोगों की जान जा चुकी है।समिति ने गड्ढों, खुले नालों, मैनहोल और बिना बैरिकेड वाले जलभराव क्षेत्रों की तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए हैं।

सूचना मिलने पर 48 घंटे में भरे जाएं गड्ढे

समिति ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि चिन्हित गड्ढों की तत्काल मरम्मत की जाए तथा किसी भी खतरे की सूचना मिलने के 48 घंटे के भीतर कार्रवाई हो। साथ ही खुले मैनहोल, नालों और जलभराव वाले स्थानों पर मजबूत बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिव टेप और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। निर्देशों में कहा गया है कि सड़क निर्माण और रखरखाव भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुसार होना चाहिए। समिति ने कहा है कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले राज्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। एमपी समेत सभी राज्यों को दो महीने में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

पांच साल के हादसों का डेटा मांगा

जिला सड़क सुरक्षा समितियों को नियमित ऑडिट कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं। समिति ने राज्यों से पिछले पांच सालों में गड्ढों के कारण हुए हादसों का डेटा मांगा है। खुले जलभराव और बिना बैरिकेड वाले क्षेत्रों में हुई मौतों और घायलों की जानकारी भी मांगी गई है। इससे पहले 2018 में भी रोड सेफ्टी कमेटी ने सड़क हादसे कम करने के लिए राज्यों को कई निर्देश दिए थे। इनमें हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाने, स्पीड मॉनिटरिंग, सड़क किनारे बैरियर लगाने, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का ऑडिट और स्कूल वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे निर्देश शामिल थे।

जॉच करें, सफाई करें और ढके' थीम के साथ डेंगू मुक्त विदिशा का लिया संकल्प

राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर कलेक्ट्रेट में दिलाई गई जागरूकता शपथ

विदिशा (निप्र)। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आज शनिवार को कलेक्ट्रेट विदिशा के बेतवा सभाकक्ष में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर ने की। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामहित कुमार द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डेंगू जागरूकता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख एवं अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि प्रत्येक वर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आमजन को डेंगू रोग के प्रति जागरूक करना तथा इसकी रोकथाम एवं बचाव के उपायों की जानकारी देना है। डेंगू नियंत्रण हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से लोगों को यह समझाया जाता है कि डेंगू क्या है, यह कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं तथा इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। इस वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस की थीम 'डेंगू नियंत्रण के लिए जनभागीदारी - जॉच करें, सफाई करें और ढके' निर्धारित की गई है। इसी थीम के अनुरूप कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डेंगू मुक्त समाज निर्माण हेतु विभिन्न संकल्प दिलाए गए। शपथ के दौरान सभी ने अपने घर, कार्यस्थल एवं आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। साथ ही यह भी प्रतिज्ञा की गई कि घरों में कूलर, गमले, पुराने टायर, कबाड़ एवं अन्य पात्रों में पानी जमा नहीं होने दिया जाएगा, जिससे मच्छरों के पनपने की संभावना समाप्त हो सके। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने यह भी संकल्प लिया कि वे प्रत्येक सप्ताह घरों में जमा पानी के स्रोतों की जांच करेंगे तथा उन्हें नियमित रूप से साफ एवं सूखा रखेंगे। मच्छरों के काटने से बचाव के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनने एवं सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करने का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि डेंगू से बचाव केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है।

इसलिए सभी लोगों से अपने परिवार, मित्रों एवं पड़ोसियों को डेंगू के लक्षणों और बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने की अपील की गई। शपथ में यह भी संकल्प लिया गया कि यदि किसी व्यक्ति में तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द अथवा डेंगू के अन्य लक्षण दिखाई दें तो बिना लापरवाही किए तत्काल नजदीकी सरकारी अस्पताल या चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

सीएमएचओ डॉ. सिंह ने की राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा

हरदा (निप्र)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.पी. सिंह ने शुक्रवार को सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री दिनेश चौहान, सभी लेखापाल, बीईई, बीपीएम, बीसीएम एवं कार्यक्रम नोडल अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में शत-प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 12 सप्ताह के पूर्व अनिवार्य रूप से किया जाए। हाईरिस्क श्रेणी की महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। इनकी सूची सभी कर्मचारियों के पास उपलब्ध हो ताकि समय पर प्रबंधन हो सके। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था में माह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए, जिससे हितग्राहियों को समय पर पर्याप्त ब्लड उपलब्ध हो सके। सभी अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित स्थान से सार्थक एप पर अटेंडेंस लगाएं। जननी सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता के हितग्राहियों के प्रसव अपडेट, ई-केवाईसी व डीबीटी अपडेट कराकर समय-सीमा पर भुगतान किया जाए। समस्या वाले प्रकरणों का लेखापाल भोपाल जाकर निराकरण कराएं। टीबी मरीजों का शत-प्रतिशत चिन्हांकन कर तत्काल उपचार शुरू कराया जाए। बैठक में डॉ. सिंह ने निर्देशित किया कि सभी संस्थाओं में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश। डॉ. सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन जन-स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। सभी अधिकारी लक्ष्य अनुसार कार्य कर आमजन को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं।

राज्य प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के सदस्य ने आष्टा में ली अधिकारियों की बैठक

सीहोर (निप्र)। राज्य प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के सदस्य श्री अक्षय सिंह द्वारा आष्टा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने विभागों की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं जनहित से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों द्वारा शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन के लिए प्रशासनिक कार्यप्रणाली एवं व्यवस्थाओं को सरल, पारदर्शी और जनोन्मुख बनाने के संबंध में चर्चा की गई तथा आवश्यक सुझाव भी दिए गए।

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक सम्पन्न

नर्मदापुरम (निप्र)। जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने की। बैठक में समिति सचिव एवं सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री विवेक नागवंशी, समिति सदस्य श्रीमती सीमा कास्दे, MPRDC के सहायक महाप्रबंधक श्री दिनेश लोवंशी, क्षेत्र संयोजक हर्षित कौरव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से सिवनी मालवा वन परिक्षेत्र बनापुरा अंतर्गत ग्राम धरमकुंडी के कक्ष क्रमांक पीएफ-161 के रकबा 0.445 हेक्टेयर क्षेत्र में नर्मदापुरम-टिमरनी सड़क निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सड़क निर्माण कार्य से क्षेत्रीय आवागमन एवं विकास को मिलने वाले लाभों पर भी चर्चा की गई। समिति द्वारा आवश्यक प्रक्रियाओं का परीक्षण उपरांत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर की जांच एवं प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने एनएचएम एवं भार्गवी हेल्थ केयर के मध्य एमओयू

नर्मदापुरम (निप्र)। मध्यप्रदेश सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सतत प्रयासरत है। इसी क्रम में प्रदेश में गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर की समय पर जांच एवं प्रभावी प्रबंधन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश एवं भार्गवी हेल्थ केयर (बीजीएच), हैदराबाद के मध्य एमओयू किया गया है। यह समझौता राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहयोग पर केंद्रित है। एमओयू में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रीवा जिले में 25 से 65 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 10 हजार महिलाओं की एचपीवी डीएनए आधारित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा राज्य स्तर पर प्रभावी समन्वय के लिए एएनएम, स्टाफ नर्स, सीएचओ एवं आशा कार्यकर्ताओं का चयन एवं प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। भार्गवी हेल्थ केयर, हैदराबाद द्वारा सर्वाइकल कैंसर की जांच एवं उपचार के लिये विशेषज्ञ तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

बाढ आपदा प्रबंधन, पूर्व तैयारियों की समीक्षा

विदिशा (निप्र)। वर्षाकाल के दौरान जिले में किसी भी प्रकार की क्षति ना हो इसके लिए किए जाने वाले प्रबंधनों पर आज विचार विमर्श किया गया। प्रभारी कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर की अध्यक्षता में आहूत इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ ओपी सनोडिया के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। प्रभारी कलेक्टर श्री डामोर ने कहा कि हर विभाग को अपनी-अपनी कार्ययोजना तैयार कर इसकी प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश पूर्व में प्रसारित किए गए है जिसमें मुख्य रूप से नोड्ल अधिकारी एवं उसके सहायक का नाम एवं सम्पर्क नम्बर, बाढ़ आपदा प्रबंधन के संबंध में बचाव स्त्रोतों की जानकारी दी जानी है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की बैठक समस्त एसडीएम अपने स्तर पर आहूत करेंगे। इस दौरान बाढ़ के प्रकार, बाढ़ से खतरा, बाढ़ के प्रभाव, बाढ़ के दुष्परिणामों को बढाने वाले कारक तैयार योजना, पूर्व चेतावनी तंत्र, निर्धारित स्थलों की तैयारियां, बाढ़ के पहले की तैयारी, आपातकालीन वस्तुएं, बाढ़ के दौरान त्वरित किए जाने वाले कार्य, प्रभावितों को राहत शिविरों में ठहराने के प्रबंध, बाढ़ संबंधी चेतावनी देने, चेतावनी के उपरांत किए जाने वाले कार्य, पानी में डूबे व्यक्ति की सहायता, बाढ़ के बाद सामान्य जनजीवन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रत्येक तहसील में विभाग के माध्यम से चार-चार गोताखोर, लाइफ जैकेट, नाव मुहैया कराई गई है। उन्होंने स्थानीय स्थलों के नवीने गोताखोरो की सूची तैयार कर एक प्रति होमगार्ड कार्यालय को उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही, बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यो की चेकलिस्ट के अनुसार सभी अधिकारियों को कार्यो का संपादन कराने हेतु ताकिद किा गया हैं।

प्रभारी कलेक्टर श्री डामोर ने कहा कि जिले में जो भी जलाश्य, नदियां है जिनके माध्यम से वर्षारूपी जल बस्तियों, शहर में भरता है का चिन्हांकन पूर्व में किया जा चुका है। इसके अलावा और नए क्षेत्रों में जलभराव की संभावना हो तो उसकी सूची तैयार कर ली जाए। वर्षाकाल के दौरान स्थानीय एसडीएम, तहसीलदार सतर्क रहें और जिला कार्यालय, राज्य के बाढ़ आपदा कंट्रोल रूम से सतत सम्पर्क बनाए रखें। बांधो का पानी छोड़ने से पूर्व संबंधित क्षेत्रों के रहवासियों को चेतावनी दी जाए। बाढ़ के दौरान किसी भी प्रकार से जनहानि ना हो के प्रबंध पूर्व में सुनिश्चित किए जाए। इसी प्रकार पशु हानि भी ना हो पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित कराए जाने पर उन्होंने बल दिया। प्रभारी कलेक्टर श्री डामोर ने कहा कि जिन विभागों की सड़कों पर पुल-पुलिया है कि सूची तैयार की जाए और बाढ़ से प्रभावित होने वाली पुल-पुलियों पर बेरीकेट् लगाने और चैकीदार तैनात करने की जबावदेही संबंधित विभाग की होगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम का गठन किया जाता है ठीक वैसे ही तहसील स्तरों पर कार्यवाही की जाए।

टीम गठन

आपदा प्रबंधन के तहत जिला मुख्यालय, तहसील, ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर टीम गठित करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। प्रत्येक टीम में पांच-पांच सदस्यों के अलावा स्थानीय गणमान्य नागरिकों को भी शामिल किया जाएगा।

उपकरणों का परीक्षण

प्रभारी कलेक्टर श्री डामोर ने बाढ़ से बचाव के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री की जांच पड़ताल पूर्व में करने के निर्देश दिए है।

नोड्ल अधिकारी

प्रभारी कलेक्टर श्री डामोर ने कहा कि प्रत्येक विभाग के नोड्ल अधिकारी वर्षाकाल अवधि में सतत सम्पर्क में बने रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अमले सहित बचाव राहत स्थल पर अविलम्ब पहुंचेगे। उन्होंने ऊर्जा विभाग और नगरपालिका की एक-एक टीम पुलिस थानों में समुचित उपकरणों सहित मौजूद रहेगी।

चेक लिस्ट पर कार्य करने के निर्देश

आगामी वर्षाकाल को ध्यानगत रखते हुए आपदा प्रबंधन के तहत पूर्व में की जाने वाली तैयारियों के परिपेक्ष्य में संबंधितों को चेक लिस्ट से अवगत कराया गया है। जिले के समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देश पत्र जारी किए है कि आपदा प्रबंधन की तैयारियों के संबंध में चैकलिस्ट पर कार्यवाही समय सीमा में करें और उसका प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

धनोरा समूह नल-जल योजना के ट्रीटमेंट प्लांट का कलेक्टर डॉ सोनवणे ने किया निरीक्षण

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने शुक्रवार को आठनेर विकासखंड के भ्रमण के दौरान धनोरा समूह नल-जल योजना के जल शुद्धिकरण संयंत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था एवं भविष्य की विस्तार योजनाओं की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। पीएचई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जल शुद्धिकरण प्लांट की क्षमता 3.76 एमएलडी है तथा वर्तमान में योजना के माध्यम से 22 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने ग्राम जावरा में पेयजल आपूर्ति की स्थिति के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि ग्राम की जनसंख्या के अनुसार 55 एलपीसीडी मानक के तहत प्रतिदिन पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2014-15 में किया गया था तथा वर्तमान में प्लांट पूर्ण क्षमता से संचालित हो रहा है। हालांकि , ग्रामों में जनसंख्या वृद्धि के कारण पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने अधिकारियों से पूछा कि प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कार्ययोजना बनाई गई है तथा क्या इसे निर्गुड़ जलाशय से जोड़ा जा सकता है।

अंतरवर्तीय खेती से बढ़ी आय, किसान बना मिसाल

विदिशा (निप्र)। प्रगतिशील कृषक श्री संग्राम सिंह दांगी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यदि किसान वैज्ञानिक सलाह और नई तकनीकों को अपनाए, तो सीमित संसाधनों में भी उत्कृष्ट उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक सोच के साथ खेती की तैयारी श्री दांगी ने फसल लगाने से पहले अपने खेत में नरवाई प्रबंधन अपनाया और फसल अवशेषों को जलाने के बजाय मिट्टी में ही मिला दिया। इससे खेत में जैविक पदार्थ और कार्बन की मात्रा बढ़ी, जो मिट्टी की उर्वरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंतरवर्तीय फसल प्रणाली का सफल प्रयोग आत्मा परियोजना के अंतर्गत फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन में उन्होंने 1 एकड़ क्षेत्र में मसूर और अलसी की अंतरवर्तीय फसल लगाई। जिसमें मसूर बीजः 20 किलो और अलसी बीजः 2.5 किलो शामिल रहा। इस आधुनिक पद्धति से उन्होंने भूमि का बेहतर उपयोग किया और जोखिम को भी कम किया।

उत्पादन और परिणाम

उम्मीद से बढ़कर सफलता इस प्रयोग से उन्हें शानदार उत्पादन प्राप्त हुआ। यह उत्पादन न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रहा, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण बन गया।

तकनीकी मार्गदर्शन

सफलता की असली कुंजी श्री दांगी बताते हैं कि बीज बुवाई से लेकर कटाई तक उन्हें कृषि विभाग, आत्मा परियोजना के अंतर्गत मार्गदर्शन में निरंतर तकनीकी सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि 'आत्मा परियोजना से उन्हें निरंतर नई जानकारी मिलती है, जिसे वह अपने खेत में अपनाकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) से बढ़ी मिट्टी की सेहत- श्री दांगी ने एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन अपनाते हुए जैविक और अजैविक दोनों विधियों का संतुलित उपयोग किया। जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ी, उत्पादन में कमी नहीं आई, फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

अब प्राकृतिक खेती की ओर कदम

कि कृषक श्री दांगी बताते हैं कि नरवाई प्रबंधन और आईएनएम अपनाने से उनके खेत में कार्बन की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस सकारात्मक बदलाव को देखते हुए अब वे अपने खेत में पूरी तरह प्राकृतिक खेती अपनाने का निर्णय ले चुके हैं। उनके प्रेरणादायक विचार हैं कि 'जो किसान सीखता है, वही आगे बढ़ता है।' 'मिट्टी की सेहत ही किसान की असली संपत्ति है।' 'वैज्ञानिक सोच और प्राकृतिक संतुलन से ही समृद्ध खेती संभव है।' 'नई तकनीक + सही मार्गदर्शन = दोगुनी सफलता है' निष्कर्ष - श्री संग्राम सिंह दांगी की यह सफलता कहानी बताती है कि यदि किसान वैज्ञानिक विधियों, अंतरवर्तीय खेती और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को अपनाए, तो वह कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त कर सकता है। यह कहानी अन्य किसानों के लिए एक प्रेरणा है कि वे भी नई तकनीकों को अपनाकर अपनी खेती को लाभकारी बनाएं।

विधायक श्री मुकेश टंडन ने कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

किसानों को नवीन कृषि तकनीकों एवं योजनाओं की जानकारी देने गांव-गांव पहुंचेगा कृषि रथ

विदिशा (निप्र)। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, विभागीय योजनाओं तथा प्राकृतिक एवं उन्नत खेती के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज नई कलेक्ट्रेट भवन परिसर से कृषि रथ को स्थानीय विधायक श्री मुकेश टंडन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

कार्यक्रम में प्रभारी कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर, उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग श्री के.एस. खपेड़िया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक श्री विनय सिंह, सहायक संचालक कृषि श्री आर.जी. रजक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जिले के प्रगतिशील कृषक उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक श्री मुकेश टंडन ने कहा कि कृषि रथ के माध्यम से किसानों तक शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं, आधुनिक कृषि पद्धतियों, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण, उन्नत बीज, सिंचाई प्रबंधन तथा कृषि यंत्रीकरण संबंधी जानकारियां पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए किसानों को नई तकनीकों से जोड़ना आवश्यक है।

प्रभारी कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर ने बताया कि कृषि रथ जिले के विभिन्न ग्रामों में भ्रमण कर किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देगा तथा कृषि विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान से जुड़कर लाभ लेने की अपील की।

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने कृषि रथ में प्रदर्शित प्रचार सामग्री, तकनीकी जानकारी एवं जनजागरूकता संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।

पिता के निधन उपरांत नेत्रदान कराकर पुत्रों ने दिया मानवता का संदेश

सीहोर (निप्र)। सीहोर के चाणक्यपुरी निवासी श्री सुनील चौहान एवं श्री अनिल चौहान ने अपने पिता स्वर्गीय श्री शिवराज सिंह चौहान के निधन के उपरांत नेत्रदान कराकर मानवता और सामाजिक संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। दुःख की इस घड़ी में दोनों पुत्रों ने समाज को प्रेरणा देने वाला निर्णय लेते हुए स्वप्रेरणा से नेत्रदान कराने की इच्छा व्यक्त की। सिविल सर्जन डॉ यूके श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार की सहमति के बाद भोपाल स्थित गाँधी मेडिकल कॉलेज के नेत्र बैंक की टीम द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर नेत्रदान संपन्न कराया गया। उन्होंने कहा कि नेत्रदान महादान है और इससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में फिर से रोशनी लाई जा सकती है। समाज में ऐसे उदाहरण लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विकासखंड नटेरन के कृषि उपज मंडी शमशाबाद में हुआ कृषि रथ का शुभारंभ

विदिशा (निप्र)। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है, कृषि वर्ष 2026 के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 को दृष्टिगत रखते हुए विकासखंड नटेरन के कृषि उपज मंडी परिसर शमशाबाद में कृषि रथ कार्यक्रम का शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री प्रदीप माहेश्वरी, एसडीएम श्री अजय प्रताप सिंह पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री जगदीश गुर्जर एवं प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री कुंदन सिंह की उपस्थिति में किया गया। कृषि रथ के माध्यम से किसानों तक पहुंचेगी आधुनिक कृषिगत जानकारी - विदिशा जिले के प्रत्येक विकासखंड अंतर्गत निर्धारित ग्राम पंचायतों में कृषि रथ का नियमित भ्रमण

किया जाएगा। प्रतिदिन ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि रथ के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध विभागों जैसे पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन आदि से संबंधित योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाएगी। इस दौरान किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित कर नवीन एवं वैज्ञानिक तकनीकी सुधारों की जानकारी दी जाएगी। विभिन्न कृषिगत गतिविधियों से कृषि हुए रूबरू - कृषि रथ के माध्यम से विकासखंड तकनीकी प्रबंधक श्री नरेंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन, कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय, फसल विविधीकरण, विभागीय कृषि योजनाओं का प्रचार-प्रसार, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, ई-विकास प्रणाली अंतर्गत ई-टोकन उर्वरक वितरण व्यवस्था तथा पराली प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। कृषकों ने किया गया संवाद - कृषि रथ शमशाबाद पहुंचा, जहां उपस्थित कृषकों के साथ कृषि विस्तार अधिकारी श्री सत्यम नेमा द्वारा नई ई-टोकन उर्वरक वितरण व्यवस्था एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं पर चर्चा की गई।

किसानों ने योजनाओं में गहरी रुचि दिखाई और अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। कृषि रथ अभियान के माध्यम से जिले के किसानों को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं लाभकारी खेती की दिशा में प्रेरित कर किसान कल्याण वर्ष 2026 को सार्थक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान कृषि उपज मंडी परिसर में कृषि विभाग से कृषि विस्तार अधिकारी श्री रजत जैन, श्री अभिषेक जैन, श्री लक्ष्मण गुर्जर, श्री विकास शाक्य, मंडी से श्री जगमोहन शर्मा उपस्थित रहे।

कुर्सी मिलने से पहले ही छिनी!

मोहन का मंत्रालय

आशीष चौधरी

डॉ. मोहन यादव सरकार में मलाईदार कुर्सियों निगम-मंडल और प्राधिकरण के लिए जो कतार लगी थी, उस पर फिलहाल 'नो एंट्री' का बोर्ड लटक गया है। वजह हमारे नए-नवेले अध्यक्षों का 'अति-उत्साह'। दिल्ली से प्रधानमंत्री चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि सादगी अपनाओ, वीआईपी कल्चर छोड़ो, लेकिन अपुन के नेताओं को तो जब तक सौ गाड़ियों का काफिला और ढोल-ताशे न मिलें, तब तक अध्यक्ष बनने का फील ही नहीं आता! ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया कि प्रधानमंत्री की अपील की धज्जियां उड़ गईं। नतीजतन, संगठन ने ऊपर से ऐसा 'पावर कट' किया कि करीब दर्जनभर विभागों के निगम मंडल और प्राधिकरण की नियुक्तियां ठंडे बस्ते में चली गईं। अब ज्ञान यह दिया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विचार करेंगे, पर सच तो यह है कि 'ज्यादा उड़ोगे, तो पर कतर दिए जाएंगे' वाला सबक बखूबी सिखा दिया गया है।

'रिटायरमेंट' सिर्फ कागजों में, पावर तो परमानेंट है!

सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन कुछ नौकरशाहों की किस्मत के सितारे कभी गर्दिश में नहीं आते। एक रिटायर्ड आईएएस साहब इन दिनों सरकार में ऐसे छाए हुए हैं जैसे पूरी ब्यूरोक्रेसी का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास हो। पहले भी सरकार के 'कृपा पात्र' थे, और आज भी 'परम प्रिय' बने हुए हैं। साहब ने पिछले दिनों एक ऐसा 'पावरफुल' आदेश जारी कर दिया कि अच्छे-अच्छे सिटिंग अफसरों के पसीने छूट गए। गलियारों में कानाफूसी हो रही है कि भाई, रिटायरमेंट के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो ठीक थी, पर क्या सरकार चलाने की चाबी भी इन्हीं को सौंप दी गई है? अनुभव का लाभ लेने के नाम पर जो जलवा चल रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि साहब 'सुपर' मोड में आ चुके हैं। अब देखना यह है कि यह अमरूद जैसी मीठी 'कृपा' कब तक बरसती है!

वार भी 'गरिमा' वाला और चंदे का 'अहंकार' भी!

राजनीति में जब दो धुर विरोधी आमने-सामने हों, तो अमूमन तलवारें खिंच जाती हैं। लेकिन मालवा की धरती पर पिछले दिनों एक गजब का 'सनातनी ड्रामा' देखने को मिला। एक पूर्व मुख्यमंत्री का सामना सत्ता पक्ष की एक 'फायर ब्रांड' नेत्री से हो गया। फिर क्या था? दोनों ने एक-दूसरे को 'सनातन' के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। कटाक्ष इतने तीखे थे कि मिर्च भी शर्मा जाए, लेकिन मजाल है कि जुबान की मर्यादा टूटी हो! हंसी-मजाक और आत्मीयता के लपेटे में ऐसे तीर चले कि देखने वाले कायल हो गए। बात यहीं नहीं रुकी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने तो अयोध्या राम मंदिर के चंदे को लेकर भी 'नंबर गेम' खेल दिया। उन्होंने तंज कसते हुए याद दिला दिया कि मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने सत्ता पक्ष के ही एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री से कहीं ज्यादा बड़ी रकम दान की है।

मंत्रियों को सताने लगा 'प्रमोशन' का डर!

मध्य प्रदेश की राजनीति में आजकल एक नया खौफ पैदा हो गया है–'दिल्ली का बुलावा'। राज्यसभा की खाली हो रही 3सीटों को लेकर सरगर्मी तेज है। चर्चा है कि केंद्रीय नेतृत्व, राज्य के किसी मंत्री को उठाकर सीधे दिल्ली राज्यसभा या संगठन में लैंड कराने की तैयारी में है। एक नाम 'पश्चिम' मालवा-निमाड़ से तैर रहा है, तो दूसरा राजधानी भोपाल सम्भाग का है। वैसे तो इसे 'प्रमोशन' कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसे 'राजनैतिक विस्थापन' ज्यादा माना जाता है। विधायकों के संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की दो सीटें तो पक्की हैं, इसलिए वहां से किसे 'रवाना' करना है, इसकी स्क्रिप्ट तैयार है। उधर, कांग्रेस अपनी इकलौती सीट बचाने के लिए ऐसे हाथ-पैर मार रही है जैसे डूबते को तिनके का सहारा! देखना दिलचस्प होगा कि किसका पत्ता कटता है और किसकी लॉटरी लगती है। बता दे कि अगले माह प्रदेश की तीन राज्यसभा सीट खाली हो रही हैं। राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, डॉ. समर सिंह सोलंकी और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कोरियन का कार्यकाल खत्म हो रहा है।

जल संकट, गुस्सा सड़कों पर उतरा विधायक ने महापौर को चेताया

गौरी नगर में चक्काजाम, नारेबाजी, पानी को लेकर आक्रोश बढ़ा

इंदौर। शहर में लगातार गहराते जल संकट ने अब राजनीतिक और जन आक्रोश का रूप लेना शुरू कर दिया है। एक ओर वार्ड-20 के गौरी नगर में पानी नहीं मिलने से रहवासियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। दूसरी ओर भाजपा विधायक महेंद्र हार्डिया ने भी अपनी ही पार्टी के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को खुली चेतावनी दे दी। शहर के कई इलाकों में एक दिन छोड़कर पानी मिलने, गंदे पानी की आपूर्ति और टैंकरों की कमी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सोमवार को गौरी नगर में पानी की समस्या को लेकर हालात अचानक बिगड़ गए। लंबे समय से पानी की किल्लत झेल रहे रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्षद यशस्वी अमित पटेल और पार्षद राजू भदौरिया भी रहवासियों के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुए। देखते ही देखते खातीपुरा क्षेत्र में जाम की स्थिति बन गई और लोगों ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी

की। प्रदर्शन में युवक कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित पटेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। रहवासियों का कहना था कि नगर निगम को पहले से जल संकट की आशंका थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस तैयारी नहीं की गई। कई इलाकों में एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है, जबकि लोगों से पूरे महीने का शुल्क लिया जा रहा है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि सुबह गंदा पानी आता है और बाद में बहुत धीमी गति से आपूर्ति होती है।

इंदिरा नगर में भी बढ़ी परेशानी

वार्ड-71 स्थित समाजवादी इंदिरा नगर में भी जल संकट गहराता जा रहा है। यहां रहवासियों ने पार्षद हरप्रीत कौर लुथरा को अपनी समस्या बताई। लोगों का कहना है कि जिन बोरिंगों से अब तक पानी मिल रहा था, वे भी इस बार सूख चुके हैं। शहर के अलग-अलग हिस्सों में लगातार बढ़ती परेशानी के कारण लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

बढ़ते संकट से निगम पर सवाल

शहर में लगातार बढ़ते जल संकट ने नगर निगम की तैयारियों और व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रहवासी स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधियों के तेवर भी अब तीखे होने लगे हैं। आने वाले दिनों में पानी की समस्या को लेकर विरोध और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

रोज महापौर निवास पर बैठूंगा

जल संकट को लेकर भाजपा विधायक महेंद्र हार्डिया का बयान भी चर्चा में आ गया है। बताया जा रहा है कि वार्ड-41 में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रहवासियों ने विधायक के सामने पानी की समस्या को लेकर नाराजगी जताई। कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मौजूद थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि विधायक बीच कार्यक्रम से लौट गए। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक हार्डिया ने कहा कि उन्होंने शहर में पहले कभी जल संकट के इतने खराब हालात नहीं देखे। उन्होंने कहा कि टंकियां खाली पड़ी हैं और टैंकर भी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। हार्डिया ने महापौर को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे रोज महापौर निवास पर जाकर बैठेंगे।

स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर और सूरत को टक्कर देने मैदान में उतरा भोपाल, 106 नोडल अफसरों ने संभाला मोर्चा

भोपाल (नप्र)। स्वच्छ सर्वेक्षण में देश के सबसे साफ शहरों की सूची में टॉप पर आने के लिए भोपाल नगर निगम ने अपनी रणनीति बदल दी है। भोपाल ने अब सुपर स्वच्छ लीग में एंट्री कर ली है, जहां उसका सीधा मुकाबला इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, अहमदाबाद, विजयवाड़ा और लखनऊ जैसे मजबूत दावेदारों से है। इस कड़े मुकाबले को देखते हुए बीएमसी कमिश्नर संस्कृति जैन खुद मैदान में उतरी हैं और उनके निर्देशन में 106 नोडल अधिकारियों को सीधे ग्राउंड जीरो पर तैनात किया गया है।

लापरवाही पर गिरेगी गाज

नगर निगम के इस अभियान का असर अब शहर की उन तंग गलियों और सरकारी क्वाटर्स के पीछे वाले हिस्सों में दिखने लगा है, जो कभी गंदगी और बदबू का केंद्र हुआ करते थे। बीएमसी के सफाई कर्मचारी अब सूरज उगने से पहले ही सड़कों पर धूल साफ करने, गड्ढों को भरने और दीवारों की पुताई करने में जुट जाते हैं। कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि काम में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी सख्ती के तहत पिछले हफ्ते वार्ड में गंदगी मिलने पर दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और कई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

क्या है भोपाल नगर निगम का एक्शन प्लान?

निगम के पास भले ही इंदौर जैसे प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में संसाधन कम हों, लेकिन कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं। अशोका गार्डन, गिन्नोरी, नारायण नगर और बिजली नगर जैसे इलाकों के निवासियों ने भी माना है कि अब सड़कों पर कचरा साफ दिख रहा है और सुंदर दीवारें मोहल्ले को चमका रही हैं। उत्कृष्ट काम करने वाले फील्ड वर्कर्स को इस बार विशेष रूप से सम्मानित भी किया जाएगा।

प्रदेश में गर्मी के भीषण तेवर

रात में भी हीट स्ट्रोक का खतरा, कई शहरों में असामान्य स्थिति

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में मई की भीषण गर्मी अब केवल दिन तक सीमित नहीं रही, बल्कि रातें भी लगातार गर्म होती जा रही हैं। भारतीय मौसम विभाग अनुसार प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज हुआ है, जिससे वार्म नाइट यानी 'गर्म रात्रि' जैसी स्थिति बनने लगी है। बड़वानी में रात का तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा जो असामान्य है। बीते रोज राजगढ़ में भी यही हाल था।

मध्य प्रदेश में राजगढ़ में जहां दिन का पारा 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो रात का पारा भी सामान्य से 6 डिग्री अधिक 30 डिग्री था। वहीं बड़वानी जिले का तालुन में रात का तापमान 31.5 डिग्री रहा। यह सामान्य से काफी अधिक है। प्रदेश के शिवपुरी, शाजापुर गिरवर, नीचम इंदौर और सागर जिले में रात का तापमान 29 से 30 डिग्री पहुंच गया है। आईएमडी के अनुसार यह स्थिति असामान्य और खतरनाक है।

प्रदेश के सबसे गर्म शहरों में तापमान

राजगढ़ 45.0 डिग्री
रतलाम 44.8 डिग्री
विदिशा 44.6 डिग्री
खंडवा 44.5 डिग्री
छतरपुर 44.4 डिग्री

प्रदेश के 5 सबसे वार्म नाइट वाले स्थान

तालुन बड़वानी 31.5 डिग्री
शिवपुरी 29.8 डिग्री
गिरवर शाजापुर 29.5 डिग्री
मरूखेड़ा नीमच 29.4 डिग्री

रात का बढ़ता तापमान गंभीर संकेत है

जलवायु परिवर्तन के मौजूदा दौर में गर्म रातों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पहले जहां केवल दिन का अधिकतम तापमान चिंता का विषय होता था, वहीं अब रात का बढ़ता तापमान भी गंभीर संकेत माना जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में प्री-मानसूनी गतिविधियां सक्रिय नहीं हुईं, तो मध्यप्रदेश में गर्म रातों का असर और अधिक बढ़ सकता है।

वार्म नाइट काफी खतरनाक हो सकती हैं

डॉ. नायक का कहना है कि, गर्म रातें स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। सामान्यतः रात में तापमान कम होने पर शरीर को गर्मी से उबरने का मौका मिलता है, लेकिन जब रात भी गर्म बनी रहे तो शरीर को राहत नहीं मिलती। इससे हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, थकान, बेचैनी और नींद संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है।

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

क्या मई के अंतिम सप्ताह में होगा साय मंत्रिमडल में फेरबदल

छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय मंत्रिमडल में मई के अंतिम सप्ताह में फेरबदल की चर्चा चल रही है। इस फेरबदल में चार मंत्रियों की छुट्टी और कुछ के विभाग बदले जाने की खबर चल रही है। प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप में बदलाव से साय मंत्रिमडल में फेरबदल की खबर को बल मिला है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से लौटने के बाद नितिन नबीन की टीम की घोषणा होगी। प्रधानमंत्री 20 मई को विदेश से लौटेंगे। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद साय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। सुनने में आ रहा है कि नितिन नबीन की टीम में राज्य के एक मंत्री जा सकते हैं। इस महीने साय सरकार को करीब-करीब ढाई साल हो जाएगा। नए लोगों को मंत्रिमडल में जगह मिलती है तो करीब ढाई साल काम करने का उन्हें भी मौका मिल जाएगा। बताते हैं संगठन स्तर पर कई मंत्रियों की शिकायतें पहुंच रही हैं। कुछ मंत्रियों की कार्यशैली को लेकर वरिष्ठ विधायक और पार्टी के कुछ नेता नाखुश चल रहे हैं। इस कारण बदलाव के कयास का बादल छा रहा है। 17 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले अमित शाह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा दिल्ली में मुलाक़ात भी कर चुके हैं।

शक्ति संतुलन या कोई गणित ?

प्रदेश बीजेपी के कोर ग्रुप से विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमनसिंह,वरिष्ठ नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल,मंत्री रामविचार नेताम,पुन्नूलाल मोहिले, विक्रम उसेंडी,रेणुका सिंह और कुछ नेता हटा दिए गए हैं। अब कोर ग्रुप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी,लता उसेंडी, अमर अग्रवाल, शिवरतन शर्मा और कुछ नए चेहरे आ गए हैं। कोर ग्रुप पार्टी की नीति निर्धारक ईकाई है। इसमें बदलाव सुर्ख़ियों में है। सबसे ज्यादा चर्चा सांसद बृजमोहन अग्रवाल को कोर ग्रुप से अलग किए जाने पर हो रही है। बृजमोहन अग्रवाल को पहले साय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाकर सांसद का चुनाव लड़ा दिया गया। अब संगठन के नीति निर्धारक ईकाई से भी दूर कर दिया गया। कोर ग्रुप में बृजमोहन खेमे के माने जाने वाले शिवरतन शर्मा कोर ग्रुप का सदस्य बनाया गया है। आठ बार के विधायक और प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीतने वाले सांसद बृजमोहन अग्रवाल की संगठन के महत्वपूर्ण विंग से छुट्टी को उनके राजनीतिक पराभव के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय तक पार्टी कोषाध्यक्ष का काम संभालने वाले गौरीशंकर अग्रवाल भी अब कोर ग्रुप में नहीं रहेंगे। दोनों अग्रवालों की जगह अब अमर अग्रवाल ने ले लिया है। रामविचार नेताम, विक्रम उसेंडी और रेणुका सिंह की भरपाई लता उसेंडी से की गई है। लता उसेंडी ने ट्राइबल और महिला कोटा को फुलफिल कर दिया। कोर ग्रुप में बदलाव को शक्ति संतुलन के रूप में देखा जा रहा है।

अंतत : गौतम बने डीजीपी

करीब 15 महीने प्रभारी डीजीपी रहने के बाद अरुणदेव गौतम राज्य के स्थायी डीजीपी बन गए।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छत्तीसगढ़ यात्रा और 19 मई को शाह की अध्यक्षता में बस्तर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक के पहले स्थायी डीजीपी की नियुक्ति को बड़ा फैसला माना जा रहा है। कहते हैं स्थायी डीजीपी को लेकर 1992 बैच के आईपीएस गौतम और 1994 बैच के आईपीएस हिमांशु गुप्ता में कश्मकश था। बताते हैं गुप्ता गृहमंत्री विजय शर्मा की पसंद थे, हिमांशु गुप्ता को डीजीपी बनाने में पेंच था। हिमांशु से वरिष्ठ पवनदेव और जीपी सिंह हैं। खबर है कि किसी भी तरह का विवाद टालने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रभारी डीजीपी अरुणदेव गौतम को स्थायी डीजीपी बना दिया। स्थायी डीजीपी को लेकर सरकार को 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी देना है। अरुणदेव गौतम जुलाई 27 में रिटायर होंगे, उन्होंने जब से प्रभारी डीजीपी का काम संभाला हैं तब से उन्हें सरकार ने स्थायी डीजीपी मान लिया है। माना जा रहा है कि गौतम साहब रिटायरमेंट तक डीजीपी रहेंगे।

पिंगुआ तीसरी बार फारेस्ट में

सरकार ने 1994 बैच के आईएएस एसीएस मनोज पिंगुआ को तीसरी बार वन विभाग में पदस्थ किया है। पिछली सरकार में मनोज पिंगुआ के पास गृह और जेल के साथ वन और स्वास्थ्य विभाग का चार्ज भी था। 1994 बैच के आईएएस विकासशील को राज्य का मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद मनोज पिंगुआ भारत सरकार में जाने का आवेदन दिया। राज्य सरकार से एनओसी भी मिल गई। बताते हैं कई महीनों से भारत सरकार में पोस्टिंग के इंतजार में रहे मनोज पिंगुआ अब दिल्ली जाना एक साल के लिए स्थगित कर दिया है। एनओसी वापस होने के बाद सरकार ने मनोज पिंगुआ को गृह से वन विभाग में भेज दिया। वन विभाग को अच्छे से जान और समझ चुके मनोज पिंगुआ के सामने अब बड़ी चुनौती राज्य के लिए नए वन प्रमुख का चयन है।

डीजी-एडीजी से जूनियर होम सेक्रेटरी

सरकार ने 1997 बैच की आईएएस निहारिका बारिक सिंह को प्रमुख सचिव गृह बनाया है। गृह विभाग में ही पुलिस महकमा आता है। पुलिस महकमे में डीजीपी अरुणदेव गौतम 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं। डीजी स्तर के अधिकारी और पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के चेयरमैन और एमडी पवन देव भी 1992 बैच के आईपीएस हैं। डीजी जेल हिमांशु गुप्ता और डीजी जीपी सिंह 1994 बैच के हैं एडीजी प्रशासन एसआरपी कल्लूरी, एडीजी प्रदीप गुप्ता और एडीजी विवेकानंद भी निहारिका बारिक से सीनियर हैं। एसआरपी कल्लूरी 1994 बैच के आईपीएस हैं तो प्रदीप गुप्ता 1995 और विवेकानंद 1996 बैच के आईपीएस हैं। सरकार ने महिला आईएएस को प्रमुख सचिव गृह बनाकर नारी शक्ति का सम्मान तो किया है, साथ में नया संदेश देने की कोशिश की है, पर सीनियर आईपीएस अपने से जूनियर आईएएस अफसर की बैठक में जाएंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल है। निहारिका बारिक सिंह की गृह विभाग में पोस्टिंग के साथ अब यहां अफसरों का दबदबा हो गया है। आईपीएस नेहा चंपावत गृह विभाग में सचिव हैं।

बीजेपी नेता का आशीर्वाद

कहते हैं पिछले दिनों रायपुर के एक चर्चित जिम पर जीएसटी का छापा पड़ने वाला था, लेकिन जिम के मालिक को बीजेपी के एक नेता का आशीर्वाद मिल गया और जिम पर छापा टल गया। बताते हैं जिम एक बड़े शॉपिंग माल में है। इस जिम में कई वीआईपी और राजनेता सुबह-शाम कसरत करने जाते हैं। इस जिम में कांग्रेस राज में चर्चित एक व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट भी है। अब बीजेपी के राज में जिम मालिक ने बीजेपी के नेता को अपना शुभचिंतक बना लिया। यह फार्मूला काम आया जिम पर जीएसटी का रेड टल गया। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी नेता ने जिम को कार्रवाई से बचाने के लिए एड़ी-चोंटी जोर लगा दिया।

ओपी का सिक्सर

प्रधानमंत्री के पेट्रोल-डीजल खपत कम करने की अपील के तत्काल बाद राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सबसे पहले अपने काफिले में वाहन कम करने का ऐलान कर बाजी मार ली। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपने काफिले में गाड़ियां कम करने का निर्देश दिया। आईएएस से राजनीति में आए चौधरी जी ने वह कर दिया, जो दूसरे मंत्री नहीं कर पाए। ओपी चौधरी ने मौके का फायदा उठा लिया। अब सरकार ने मितव्ययता के फरमान जारी कर दिए हैं। पेट्रोल-डीजल की जगह ईवी वाहनों के इस्तेमाल के साथ सरकारी विदेश दौरों पर भी रोक लगा दी गई। अब देखते हैं सरकार और क्या-क्या खर्च में कटौती करती है।

फिर भारी पड़े भूपेश बघेल ?

कहा जा रहा है महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष बनाई गई संजारी बालोद की विधायक संगीता सिन्हा भूपेश बघेल खेमे की है। कहते हैं टीएस सिंहदेव छन्नी साहू को महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी दिलाने में लगे थे,पर संगीता सिन्हा के नाम पर मुहर लग गई। बताते हैं महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद संगीता सिन्हा सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने गई थी। बताते हैं जिलाध्यक्षों के चुनाव में भी भूपेश बघेल का पलड़ा भारी रहा। पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों के चुनाव निपटने के बाद अब उम्मीद की जा रही कि छत्तीसगढ़ को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष किसी आदिवासी नेता को ही बनाते हैं या फिर सामान्य वर्ग से, यह बड़ा सवाल है। टीएस सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में हैं। सामान्य वर्ग से पीसीसी चीफ बनाते हैं तो सिंहदेव का नंबर लग जाएगा। आदिवासी या ओबीसी का फार्मूला चला तो सिंहदेव पीछे छूट जाएंगे।

कौन बनेगा पीसीसीएफ

उम्मीद की जा रही है कि राज्य के नए पीसीसीएफ और वन बल प्रमुख के लिए अगले हफ्ते डीपीसी हो जाएगी। वैसे डीपीसी मई के पहले हफ्ते में होनी थी, पर टल गई। वर्तमान पीसीसीएफ और वन बल प्रमुख वी श्रीनिवास राव 31 को रिटायर होने वाले हैं। 30 और 31 मई को छुट्टी है, ऐसे फैसला 29 मई या उसके पहले करना होगा। नए पीसीसीएफ और वन बल प्रमुख के लिए अरुण पांडे के साथ ओपी यादव दौड़ में हैं। लेकिन वी श्रीनिवास राव के सेवा विस्तार की भी चर्चा है। वी श्रीनिवास राव को भूपेश बघेल के राज में पीसीसीएफ और वन बल प्रमुख बनाया गया था और वे साय सरकार में भी करीब सवा दो साल बिना बाधा के चल गए। राव के सरकार और भाजपा के बड़े नेताओं से मधुर रिश्ते बताए जाते हैं। कहा जा रहा है कि श्रीनिवास राव को एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो अरुण पांडे को वन विभाग के मुखिया की कुर्सी मिल जाएगी। अरुण पांडे को मुख्यमंत्री की पसंद बताया जा रहा है।